लखनऊ

हिंदी दैनिक

आर्यावर्त क्रांति

शनिवार, 26 जुलाई, 2025
वर्ष : 11 । अंक: 17
मूल्य : 1 रुपये
पृष्ठ : 8

UPHIN/2014/57034

प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह याद रखना बेहतर होगा कि सभी सफल व्यवसाय नैतिकता की नींव पर आधारित होते हैं। - हैनरी वार्ड बीचर

TODAY WEATHER

DAY 37° Hi | NIGHT 26° Low

संक्षेप

स्वर्ण मंदिर धमकी मामला : कांग्रेस ने केंद्र और पंजाब सरकार से मांगी जवाबदेही

पंजाब। अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी का मुद्दा दिल्ली में संसद तक पहुंचा है। कांग्रेस सांसदों ने गुरुवार को पंजाब सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाए और केंद्रीय गृह मंत्री से मामले की जांच कराने की मांग की। कांग्रेस सांसद अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने कहा, लगातार ईमेल आ रहे हैं। एक व्यक्ति पकड़ा गया, लेकिन गिरफ्तारी के बाद भी ईमेल आते रहे। उन्होंने कहा कि गलत व्यक्ति पकड़ा गया है और धमकी दी कि वे हरमंदिर साहिब (स्वर्ण मंदिर) को उड़ा देंगे। राजा वड़िंग ने आगे कहा, हम चाहते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री इस पर बात रखें और बताएं कि कौन धमकी दे रहा है? पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा, हरमंदिर साहिब (स्वर्ण मंदिर) को कई बार बम से उड़ाने की धमकी मिली है, लेकिन न पंजाब सरकार और न ही केंद्र सरकार कोई कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा, एक आदमी पकड़ा गया, उसके बाद भी धमकी आई। कहा गया कि गलत आदमी पकड़ा है, जो धमकियां दे रहे हैं, वे अलग लोग हैं। आखिर कौन लोग हैं, जो धमकियां दे रहे हैं? इनकी शिनाख्त होनी चाहिए और उन्हें पकड़कर जेल में भेजना चाहिए। चरणजीत सिंह चन्नी ने सवाल उठाया कि सिखों का सबसे पवित्र स्थान अमृतसर में हरमंदिर साहिब है, अगर वह सुरक्षित नहीं है, तो पंजाब में कौन सुरक्षित हो सकता है? इसी तरह कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह औजला ने मामले को उठाया। उन्होंने कहा कि हरमंदिर साहिब को लगातार बम से उड़ाने की धमकियां मिली हैं। एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उन्होंने एक और ईमेल भेजकर कहा कि गलत व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले, गुरजीत सिंह औजला ने लोकसभा में स्वर्ण मंदिर को धमकी मामले पर स्थगन प्रस्ताव दिया था। उन्होंने स्वर्ण मंदिर को लेकर उभरते खतरों पर तत्काल कार्रवाई और स्पष्टता की मांग की थी।

विरोध के बीच देश में होगा मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण का काम, ईसीआई ने कहा- जल्द जारी होगा शेड्यूल

नई दिल्ली। चुनाव आयोग द्वारा बिहार में किए जा रहे मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण का विपक्ष द्वारा संसद से लेकर सड़क तक विरोध किया जा रहा है। भारी विरोध के बावजूद चुनाव आयोग ने शुक्रवार को बड़ा एलान किया। दरअसल चुनाव आयोग ने कहा है कि देशभर में मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण का काम अब शुरू करने का फैसला किया गया है और जल्द ही इसके लिए शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। चुनाव आयोग ने बीती 24 जून को ही इस संबंध में आदेश जारी कर दिया था और कहा था कि संवैधानिक कर्तव्य के तहत और मतदाता सूची की अखंडता और सुरक्षा के लिए यह मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण का काम किया जाएगा। अब चुनाव आयोग ने उसकी शुरुआत कर दी है। चुनाव आयोग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि 'मतदाता सूची की अखंडता को बनाए रखना निष्पक्ष और मुक्त चुनाव के लिए आधारभूत जरूरत है। जनप्रतिनिधि कानून, 1950 और रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स, 1960 के तहत योग्यता, मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया और तरीके की जानकारी दी गई है।'

एसआईआर पर आज संसद में फिर हंगामा, राहुल-प्रियंका समेत विपक्षी सांसदों ने फॉर्म फाड़कर कूड़ेदान में डाला

नई दिल्ली, एजेंसी। देशभर में SIR के मुद्दे को लेकर सियासी सरगर्मी देखने को मिल रही है। विपक्ष की तरफ से इसको लेकर लगातार विरोध किया जा रहा है। खासतौर पर बिहार और संसद में इसका विरोध देखने को मिल रहा है। शुक्रवार को लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्ष के सांसदों ने SIR का फॉर्म फाड़कर कूडेदान में डाल दिया। इसके साथ ही सदन में भी सांसदों का हंगामा देखने को मिला। यही कारण है कि लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया।

बिहार में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभ्यास (SIR) के खिलाफ इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और नारे लगाए। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और पार्टी सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने इंडिया ब्लॉक के अन्य सांसदों के साथ मिलकर प्रतीकात्मक रूप से SIR को फाड़कर कूड़ेदान में फेंक दिया।

केंद्र संविधान का पालन नहीं कर रही- खरगे

राज्यसभा सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद परिसर में इंडिया ब्लॉक के विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रतीकात्मक रूप से SIR को फाड़कर कूड़ेदान में फेंक दिया। इस दौरान इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। बिहार SIR के खिलाफ इंडिया ब्लॉक के विरोध पर, राज्यसभा के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, "वे गरीबों को उनके मताधिकार से वंचित करना चाहते हैं और केवल कुलीन वर्ग को ही वोट देने देना चाहते हैं। वे (केंद्र सरकार) संविधान का पालन नहीं कर रहे हैं।"

उन्हें जवाब देना चाहिए – प्रियंका गांधी

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा SIR के मामले पर सरकार पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा, "सरकार को आरोपों का जवाब देना चाहिए। उन्हें हमें मतदाता सूची उपलब्ध करानी चाहिए, जिसकी हम मांग कर रहे हैं। इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। यह लोकतंत्र है। सभी राजनीतिक दलों को उस जानकारी तक पहुंच होनी चाहिए। यह जानकारी क्यों नहीं दी जा रही है?"

कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि "बीजेपी चाहेगी कि हम बिहार चुनाव का बहिष्कार करें क्योंकि उन्हें पता है कि अगर राजद और कांग्रेस साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, तो भाजपा का सफाया हो जाएगा। हम संघर्ष करेंगे और मतदाता सूची से मतदाताओं के नाम हटाने के खिलाफ आवाज उठाएंगे। हम बिहार में दो-तिहाई बहुमत से सरकार बनाएंगे।"

आपत्तिजनक और अश्लील कंटेंट परोसने पर इन 25 ओटीटी एप्स पर लगाया बैन

नई दिल्ली, एजेंसी। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) ने कथित तौर पर इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपी) को भारत भर में 25 ओटीटी ऐप्स और वेबसाइटों तक सार्वजनिक पहुँच को अवरुद्ध करने का निर्देश दिया है। ऑनलाइन अश्लील और पोर्नोग्राफिक सामग्री के प्रसार को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, ULLU, बिग शॉट्स ऐप, ALTT और देसीफ्लिक्स जैसे लोकप्रिय प्लेटफॉर्म को सामग्री उल्लंघन के कारण बंद कर दिया गया है।

स्टोरीबोर्ड18 द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अनुसार, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने पाया कि ये प्लेटफॉर्म आपत्तिजनक विज्ञापन और अश्लील सामग्री प्रदर्शित कर रहे थे - जो कई भारतीय कानूनों का उल्लंघन था। मंत्रालय ने एक आधिकारिक अधिसूचना जारी कर आईएसपी को भारतीय क्षेत्र में इन ऐप्स और वेबसाइटों तक पहुँच प्रतिबंधित करने का निर्देश दिया है।

प्रतिबंधित ओटीटी ऐप्स की सूची

ALTT, ULLU, बिग शॉट्स ऐप, जलवा ऐप, वाउ एंटरटेनमेंट, लुक एंटरटेनमेंट, हिटप्राइम, फेनियो, शोएक्स, सोल टॉकीज, कंगन ऐप, बुल ऐप, अड्डा टीवी, हॉटएक्स वीआईपी, डेसिफ्लिक्स, बूमेक्स, नवरसा लाइट, गुलाब ऐप, फुगी, मोजफ्लिक्स, हलचल ऐप, मूडएक्स, नियॉनएक्स वीआईपी, ट्रिफ्लिक्स।

केंद्र सरकार बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल के लिए कर्मचारियों को देगी विशेष छुट्टी

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्र सरकार के कर्मचारी 30 दिनों की छुट्टी का लाभ उठा सकेंगे, जिसमें 20 दिन की अर्धवेतन छुट्टी, 8 दिन की आकस्मिक छुट्टी और 2 दिन का प्रतिबंधित अवकाश शामिल है। यह जानकारी केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा सांसद सुमित्रा बाल्मीकि के सवाल के जवाब में दी। दरअसल, केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल सहित निजी कारणों के लिए प्रति वर्ष 30 दिन की अर्जित छुट्टी (ईएल), 20 दिन की अर्धवेतन छुट्टी (हाफ पे लीव), 8 दिन की आकस्मिक छुट्टी (सीएल), और 2 दिन की प्रतिबंधित अवकाश (आरएच) लेने की अनुमति दी है।

मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1972 के तहत कर्मचारी निजी कारणों (बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल) के लिए ये छुट्टियां ले सकते हैं। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को प्रति वर्ष 30 दिन की अर्जित छुट्टी, 20 दिन की अर्धवेतन छुट्टी, 8 दिन की आकस्मिक छुट्टी और 2 दिन की प्रतिबंधित अवकाश के साथ-साथ अन्य पात्र छुट्टियां दी जाती हैं, जिनका उपयोग वे किसी भी निजी कारण के लिए कर सकते हैं। 'केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1972' (1 जून 1972 से लागू हैं) में कर्मचारियों के लिए कई प्रकार की छुट्टियों का प्रावधान है।

राज्यसभा में अमित शाह का प्रस्ताव पास, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन छह महीने और बढ़ा

नई दिल्ली। मणिपुर में जारी राजनीतिक अस्थिरता के बीच केंद्र सरकार ने राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि को छह महीने के लिए बढ़ा दिया है। यह विस्तार 13 अगस्त 2025 से प्रभावी होगा। इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा प्रस्तुत सांविधिक प्रस्ताव को राज्यसभा में स्वीकार कर लिया गया है।

राज्यसभा में प्रस्तुत प्रस्ताव में कहा गया है कि यह सदन मणिपुर राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति द्वारा 13 फरवरी 2025 को जारी की गई उद्घोषणा को 13 अगस्त 2025 से छह महीने की अवधि तक जारी रखने को मंजूरी देता है। इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के साथ ही मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की दूसरी अवधि औपचारिक रूप से शुरू हो जाएगी।

जाति जनगणना अब राहुल का 'मिशन', बोले- कांग्रेस शासन में हुई गलती को सुधारूंगा

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली में कांग्रेस के 'भागीदारी न्याय सम्मेलन' को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि मैं 2004 से राजनीति में हूं। जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं, तो मुझे लगता है कि मैंने गलती की। मैंने ओबीसी की उस तरह रक्षा नहीं की जैसी मुझे करनी चाहिए थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं उस समय आपके मुद्दों को गहराई से नहीं समझ पाया। उन्होंने कहा कि मुझे अफसोस है कि अगर मुझे आपके (ओबीसी) इतिहास, आपके मुद्दों के बारे में थोड़ा भी पता होता, तो मैं उसी समय जाति जनगणना करा लेता। यह मुझसे हुई गलती है। यह कांग्रेस पार्टी की गलती नहीं है, यह मेरी गलती है। मैं उस गलती को सुधारने जा रहा हूं।

राहुल गांधी ने कहा कि मैं अपने काम के बारे में सोचता हूं कि मैंने कहां ठीक काम किया और कहां कमी रह गई, तो मुझे 2-3 बातें दिखती हैं। जमीन अधिग्रहण बिल, मनरेगा, भोजन का अधिकार, ट्राइबल बिल, नियामगिरी की लड़ाई, ये सारे काम मैंने ठीक किए। जहां तक आदिवासियों, दलितों, महिलाओं के मुद्दे हैं, वहां मुझे अच्छे नंबर मिलने चाहिए। मैंने अच्छा काम किया। कांग्रेस पार्टी और मेरे काम में एक कमी रह गई- मुझे OBC वर्ग की जिस तरह से रक्षा करनी थी, मैंने नहीं की। इसका कारण है कि मुझे OBC के मुद्दे उस वक्त गहराई से नहीं समझ आए थे। 10-15 साल पहले दलितों के सामने जो कठिनाईयां थीं, वो मुझे समझ आ गई थीं।

कांग्रेस नेता ने कहा कि उनके मुद्दे सामने हैं, वो आसानी से समझ आ जाते हैं, लेकिन OBC की मुश्किलें छुपी रहती हैं। मुझे अगर आपके मुद्दों और परेशानियों के बारे में उस वक्त पता होता तो मैं उसी वक्त जातिगत जनगणना करवा देता। वो मेरी गलती है, जिसे मैं ठीक करने जा रहा हूं। ये एक तरह से अच्छा ही हुआ, क्योंकि अगर उस समय मैंने जातिगत जनगणना करवा दी होती, तो वो आज जैसी नहीं होती।

सुप्रीम कोर्ट में यूट्यूबर का लगाई फटकार, कहा- वीडियो के आधार पर दोषी या बरी नहीं किया जाता

नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केरल के एक पत्रकार को अपने यूट्यूब चैनल 'क्राइम ऑनलाइनइ' पर एक प्रमुख महिला राजनेता के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक वीडियो प्रकाशित करने के लिए फटकार लगाई है।

न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने कहा, क्या आप चाहते हैं कि यूट्यूब वीडियो के आधार पर लोगों को दोषी ठहरा दिया जाए? सजा या बरी करने का निर्णय यूट्यूब वीडियो के आधार पर नहीं होता, वह कार्य अदालतें करती हैं। यूट्यूब पर कुछ अच्छी बातें क्यों नहीं कहते? 'क्राइम ऑनलाइन' जैसी नकारात्मक चीजें क्यों डालते हैं? केरल को 'गॉड्स ओन कंट्री' कहा जाता है, वहां की अच्छी बातों को भी बताया कीजिए।

शीर्ष अदालत ने इस दौरान पत्रकार नंदकुमार टीपी को पहले से दी गई अंतरिम जमानत की अवधि को आगे बढ़ा दिया। नंदकुमार ने इस मामले में पूर्व-गिरफ्तारी जमानत की याचिका दायर की थी। उन पर भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों के तहत महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने, धमकाने और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अश्लील सामग्री प्रसारित करने के अलावा प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के इरादे का केस दर्ज है।

केरल पुलिस ने नंदकुमार टीपी के खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 के तहत भी मामला दर्ज किया था। जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री के प्रकाशन या प्रसारण को दंडित करता है। राज्य पुलिस ने आरोप लगाया कि नंदकुमार द्वारा पोस्ट किए गए एक यूट्यूब वीडियो में महिला नेता की प्रतिष्ठा को अपमानित करने और धूमिल करने के उद्देश्य से अपमानजनक, यौन रूप से भड़काऊ और धमकी भरे बयान थे।

केरल हाईकोर्ट ने 9 जून को नंदकुमार को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया और उन्हें पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। इसके बाद पत्रकार ने हाईकोर्ट के आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी।

शस्त्र के साथ शास्त्र का भी ज्ञान जरूर, ऑपरेशन सिंदूर पर CDS चौहान का बड़ा बयान, सेना 24 घंटे तैयार है

नई दिल्ली, एजेंसी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने शुक्रवार को कहा कि पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकी संगठनों के खिलाफ भारत का सैन्य अभियान ऑपरेशन सिंदूर जारी है और सेनाएं दूसरी तरफ से किसी भी दुस्साहस के लिए चौबीसों घंटे तैयार हैं। सीडीएस चौहान ने कहा कि जैसा कि मैंने पहले कहा युद्ध में कोई दूसरा नहीं होता, और ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए, जो अभी भी जारी है; हमारी तैयारी का स्तर बहुत ऊंचा होना चाहिए। दिल्ली में एक रक्षा संगोष्ठी में बोलते हुए सीडीएस चौहान ने कहा कि प्रौद्योगिकी उन्नत हो गई है और योद्धाओं को युद्ध के तीनों स्तरों अर्थात सामरिक, परिचालन और रणनीतिक में महारत हासिल करने की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि हम प्रौद्योगिकी के निरंतर विकास से प्रेरित एक अभूतपूर्व गति देख रहे हैं। अब हम उस मोड़ पर खड़े हैं जिसे मैं सैन्य मामलों में तीसरी क्रांति कहता हूँ, जिसे मैंने अभिसरण युद्ध के रूप में गढ़ा है। युद्ध का यह रूप गतिज और अगतिज साधनों का सम्मिश्रण करता है, और पहली और दूसरी पीढ़ी के युद्ध के तत्वों को तीसरी पीढ़ी के युद्ध के साथ जोड़ता है। यह सामरिक, परिचालन और रणनीतिक क्षेत्रों का अभिसरण है। सीडीएस सिन्हा ने कहा कि यह समय है जब सेना को 'शस्त्र' (युद्ध) और 'शास्त्र' दोनों को समझना चाहिए।

पहलगाम हमले के जवाब में भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पीओके में आतंकवादी समूहों के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत जोरदार और सटीक हमले किए और नौ से ज़्यादा आतंकवादी शिविरों को नष्ट कर दिया। ये ठिकाने जैश-ए-मोहम्मद (JeM) और लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के प्रमुख कमांड सेंटर थे, जो पुलवामा (2019) और मुंबई (2008) जैसे बड़े हमलों के लिए ज़िम्मेदार थे। इस हमले में 100 से ज़्यादा आतंकवादी मारे गए। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान ने अगले तीन दिनों 8, 9 और 10 मई में भारतीय सैन्य ठिकानों पर हमले की कोशिश की। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए, भारत ने पाकिस्तान के प्रमुख सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए।

भारत में लॉन्च से पहले स्टारलिंक का सर्वर दुनिया भर में ठप, 140 देशों में इंटरनेट बाधित

नई दिल्ली, एजेंसी। एलन मस्क की महत्वाकांक्षी सैटेलाइट-आधारित इंटरनेट सर्विस स्टारलिंक को आज तड़के एक बड़े वैश्विक आउटेज का सामना करना पड़ा। एक तकनीकी खामी के चलते स्टारलिंक का सर्वर डाउन हो गया, जिससे अमेरिका और यूरोप समेत दुनिया के 140 देशों में इंटरनेट सेवाएं ठप हो गईं। सैटेलाइट इंटरनेट के लिए यह एक दुर्लभ ग्लोबल आउटेज माना जा रहा है, क्योंकि यह सर्विस अपनी भरोसेमंद कनेक्टिविटी के लिए जानी जाती है।

रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, यह समस्या स्टारलिंक के इंटरनल सॉफ्टवेयर में आई एक तकनीकी खामी की वजह से हुई। सॉफ्टवेयर फेल होने के कारण दुनिया भर में हजारों यूजर्स के डिवाइस राउटर अचानक ऑफलाइन हो गए और उनकी कनेक्टिविटी टूट गई। इंटरनेट सेवाओं को ट्रैक करने वाली वेबसाइट 'डाउनडिटेक्टर' के अनुसार, 61,000 से अधिक यूजर्स ने स्टारलिंक की सर्विस में आई इस दिक्कत को रिपोर्ट किया। भारतीय समय के अनुसार, यूजर्स ने शुक्रवार रात करीब 12:30 बजे से समस्याओं की शिकायत करना शुरू कर दिया था।

इस दुर्लभ ग्लोबल आउटेज के कारण स्टारलिंक के 60 लाख से ज्यादा यूजर्स को परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि, कंपनी की टीमों ने तेजी से काम करते हुए करीब ढाई घंटे की मशक्कत के बाद सेवाओं को फिर से बहाल कर दिया।

यह वैश्विक घटना ऐसे समय में हुई है जब स्टारलिंक भारत में अपनी सेवाएं शुरू करने की तैयारी के अंतिम चरण में है। एलन मस्क की कंपनी को भारत सरकार की ओर से फाइनल अप्रूवल मिल चुका है। अब केवल स्पेक्ट्रम आवंटन का इंतजार है, जिसके पूरा होते ही स्टारलिंक भारत में अपनी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू कर देगी। इस आउटेज ने भारत में लॉन्च से पहले सर्विस की विश्वसनीयता को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है।

बंगाली भाषा विवाद पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोली, एक और भाषा आंदोलन की ज़रूरत

नई दिल्ली। बंगाली भाषा को लेकर उठे विवाद के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक और भाषा आंदोलन का आह्वान किया और आरोप लगाया कि कई स्थानों पर बंगाली बोलने के लिए लोगों को परेशान किया जा रहा है। 'महानायक सम्मान' पुरस्कार समारोह को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि सभी को जागृत करने के लिए एक और भाषा आंदोलन की आवश्यकता है। कई जगहों पर बंगाली बोलने के कारण लोगों को परेशान किया जा रहा है। बंगाली दुनिया में पाँचवीं सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है और एशिया में दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। लगभग 30 करोड़ लोग बंगाली बोलते हैं और आज बंगाली बोलने वालों को जेल भेजा जा रहा है।

अहमदाबाद हादसे के बाद डीजीसीए का बड़ा एक्शन, एयर इंडिया को 4 कारण बताओ नोटिस ; सुरक्षा नियमों में मिलीं गंभीर खामियां

नई दिल्ली, एजेंसी। अहमदाबाद में हुए भीषण विमान हादसे के करीब एक महीने बाद, विमानन नियामक डीजीसीए ने एयर इंडिया पर शिकंजा कस दिया है। डीजीसीए ने गुरुवार को एयरलाइन को चार कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। ये नोटिस कैबिन क्रू की ड्यूटी, उनके आराम के घंटे, ट्रेनिंग और अन्य ऑपरेशनल प्रक्रियाओं में गंभीर चूकों के आरोपों को लेकर भेजे गए हैं।

सूत्रों के अनुसार, ये नोटिस 23 जुलाई को जारी किए गए, जो एयर इंडिया द्वारा ही 20 और 21 जून को स्वेच्छा से सौंपी गई रिपोर्ट पर आधारित हैं। इन रिपोर्टों में एयरलाइन ने खुद माना है कि पिछले एक साल में कई उड़ानों के दौरान सुरक्षा नियमों का उल्लंघन हुआ। डीजीसीए द्वारा जारी नोटिसों में कई गंभीर खामियों का जिक्र है। नोटिस के अनुसार, एयर इंडिया ने कम से कम चार बहुत लंबी दूरी की अंतरराष्ट्रीय उड़ानों (अल्ट्रा लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स) में केबिन क्रू के लिए अनिवार्य ड्यूटी और आराम के घंटों से जुड़े नियमों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया। इसके अतिरिक्त, कई अन्य उड़ानों में क्रू की ट्रेनिंग और तय संचालन प्रक्रियाओं में भी गंभीर लापरवाही बरती गई। डीजीसीए ने यह भी पाया कि कुछ मामलों में क्रू सदस्यों को दिए जाने वाले अनिवार्य साप्ताहिक आराम के प्रावधानों की भी अनदेखी की गई, जो उड़ान सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा है। नोटिस मिलने की पुष्टि करते हुए एयर इंडिया ने एक बयान में कहा, हमें नियामक द्वारा भेजे गए नोटिस मिले हैं, जो पिछले एक साल में हमारी स्वैच्छिक रिपोर्टिंग से संबंधित हैं। हम तय समय के भीतर इन पर जवाब देंगे।

बरेली में भीषण सड़क हादसा

ट्रक की टक्कर से ऑटो चालक की पत्नी और मासूम बेटे की मौत, मां समेत तीन घायल

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

बरेली। बरेली के फरीदपुर थाना क्षेत्र में नवादावन गांव के समीप गलत दिशा से आ रही कार से बचने के लिए चालक ने अपना ऑटो को बचाया, तभी पीछे से आ रहे ट्रक की टक्कर लगने से ऑटो आगे वाले ट्रक में जा घुसा। हादसे में ऑटो चालक की पत्नी और मासूम बेटे की मौत हो गई। तीन लोग गंभीर घायल हुए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

जानकारी के मुताबिक शाहजहांपुर के कटरा थाना क्षेत्र के गांव कपूर नगला निवासी जसवीर ऑटो चलाते हैं। उनकी बहन के घर ढकिया तिवारी गांव में शनिवार को बच्चे का नामकरण कार्यक्रम है। जिसमें छोछक (एक रस्म) ले जाने के लिए जसवीर अपने गांव से फरीदपुर कपड़े खरीदने आ रहे थे। ऑटो में वह उनकी मां रामसनेही, पत्नी पिंकी (24 वर्ष), बेटा राघव (एक वर्ष) सवार थे। उन्होंने रास्ते में खुदागंज से दो अन्य सवारियां बैठा लीं।

नवादावन गांव के समीप हुआ हादसा

नेशनल हाईवे पर फरीदपुर थाना क्षेत्र के नवादावन गांव के समीप गलत दिशा से कार आ रही थी। जसवीर ने कार से बचने के लिए ऑटो बचाया। इसी दौरान पीछे से आए ट्रक ने ऑटो को टक्कर मार दी। जिससे ऑटो आगे चल रहे ट्रक से जा टकराया। हादसे में जसवीर की पत्नी पिंकी और बेटे राघव की मौत मौके पर ही हो गई। मां रामसनेही समेत अन्य दो सवारियां गंभीर रूप से घायल हो गईं।

हादसे के बाद दोनों ट्रक व कार चालक मौके से फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को निजी एंबुलेंस से अस्पताल भिजवाया। मृतकों के शवों का पंचनामाभर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ऑटो चालक जसवीर को मामूली चोट आई है। हादसे में पत्नी-बेटे की मौत से उसका रो-रोकर बुरा हाल है।

सरकारी आदेशों की खुलेआम अवहेलना

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुल्तानपुर। योगी सरकार द्वारा स्पष्ट निर्देशों के बावजूद भी बल्दीराय तहसील सहित ब्लॉक कार्यालयों में निजी कर्मचारियों की तैनाती निरंतर बनी हुई है। सरकारी कार्यालयों में इन प्राइवेट कर्मियों की सक्रियता न सिर्फ शासनादेश की अवहेलना है, बल्कि इससे सरकारी गोपनीयता और पारदर्शिता भी प्रभावित हो रही है। जिम्मेदार अधिकारियों की अनदेखी और शिथिलता से भ्रष्टाचार को खुला समर्थन मिल रहा है।

तहसील मुख्यालय के एसडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदार कार्यालयों में कई निजी कर्मी प्रतिदिन सरकारी कर्मचारियों की तरह कार्य करते नजर आते हैं। यही नहीं, कई लेखपाल भी अपने निजी सहायकों के माध्यम से काम करा रहे हैं, जो न केवल नियमों के विरुद्ध है, बल्कि कई बार किसानों से अवैध वसूली की भी शिकायतें सामने आई हैं। धारा 24 के अंतर्गत हो रही मनमानी पैमाइश में क्षेत्र के किसानों ने आरोप लगाया है कि भूमि की पैमाइश के दौरान निजी कर्मियों द्वारा किसानों से मोटी रकम वसूली जाती है। जिन किसानों के पास देने के लिए पैसे नहीं होते, उनकी पैमाइश जानबूझकर टाल दी जाती है। ऐसे कई मामले तहसील कार्यालय में सामने आए हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ भी ठोस नहीं हुआ है।

बल्दीराय ब्लॉक कार्यालय में भी कुछ सफाईकर्मी और निजी व्यक्ति विभिन्न विभागों में बाबुओं की तरह बैठकर सरकारी कामकाज संभालते दिखाई देते हैं। कई ग्राम पंचायतों में सचिवों द्वारा भी निजी व्यक्तियों से परिवार रजिस्टर की नकल जैसे संवेदनशील कार्य करवाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर जब यह मामला उठा तो ब्लॉक कार्यालय की किरकिरी हुई, लेकिन फिर भी स्थिति में सुधार नहीं हुआ। सूत्रों का दावा है कि इन निजी कर्मचारियों को एक स्थानीय जनप्रतिनिधि का संरक्षण प्राप्त है, जिस कारण अधिकारी चाहकर भी कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं।

बल्दीराय तहसील के उपनिबंधक कार्यालय में तो स्थिति और भी गंभीर है। दो सरकारी कर्मियों के अतिरिक्त बाकी सारा कार्य निजी कर्मचारियों के द्वारा किया जा रहा है। ये निजी कर्मी न केवल बैनामा से जुड़ी गोपनीय जानकारी का दुरुपयोग करते हैं, बल्कि बैनामा लिखने से पहले कमीशन लेकर किसानों को अंदर भेजते हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार, कुछ मामलों में तो जिस भूमि पर आवास बना हुआ है, उसका बैनामा कृषि योग्य भूमि के रूप में दिखा कर किया गया, जिससे कार्यालय की साख को नुकसान पहुंचा है। कई लोगों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि उपनिबंधक कार्यालय में गोपनीयता की कोई परवाह नहीं की जाती और निजी कर्मियों द्वारा खुलेआम अनुचित कार्य कराए जाते हैं।

पुजारी बनकर जिस मंदिर में बैठा था 'कासिम', वहां हिंदू संगठन व ग्रामीणों ने पढ़ी हनुमान चालीसा

आर्यावर्त संवाददाता

मेरठ। मेरठ के दौराला थाना क्षेत्र के दादरी गांव स्थित एक मंदिर में उस समय विवाद गहरा गया, जब पता चला कि एक कासिम नामक युवक, जो एक विशेष समुदाय से जुड़ा बताया जा रहा है, नकली पुजारी बनकर मंदिर में बैठा था।

यह मामला सामने आने के बाद शुक्रवार को हिंदू संगठनों और ग्रामीणों में रोष फैल गया। हिंदूवादी नेता सचिन सिरोही के नेतृत्व में दर्जनों संगठनों के कार्यकर्ता और गांव के लोग मंदिर में पहुंचे। उन्होंने शिवलिंग पर जलाभिषेक किया, मंदिर परिसर को शुद्ध किया और हनुमान चालीसा का पाठ किया।

प्रदर्शन कर रहे लोगों ने इस घटना को आस्था से खिलवाड़ बताते हुए कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की। संगठनों का कहना था कि यह केवल धर्म का अपमान नहीं, बल्कि सांप्रदायिक सद्भाव को भी चुनौती देने की कोशिश है।

मामले में पुलिस द्वारा युवक कासिम से पूछताछ की जा रही है और सुरक्षा के दृष्टिगत गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है। फिलहाल किसी प्रकार के टकराव की स्थिति नहीं है।

प्रशासन का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए तथ्यों की जांच की जा रही है और जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी।

चंदौली के अरविंद हत्याकांड में चार आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार, चौकी प्रभारी घायल

आर्यावर्त संवाददाता

नियामताबाद (चंदौली)। बीते 21 जुलाई की रात धरना में गोलियों से भुनकर प्रॉपर्टी डीलर व जिम संचालक अरविंद यादव की हत्या करने वाले बदमाशों को गुरुवार की सुबह पुलिस ने कश्यप लाज प्रयागराज से गिरफ्तार किया। हत्या में प्रयुक्त असलहों की बरामदगी के लिए पुलिस आरोपितों के साथ ग्राम गौरी में हाईवे के किनारे खंडहरनुमा मकान (गुरुकुलम विद्यालय) पहुंची। इस बीच मौका देखकर बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस संग हुई मुठभेड़ में चार बदमाशों के पैर में गोली लग गई, जबकि चौकी प्रभारी जलीलपुर अभिषेक शुक्ला व चौकी प्रभारी रेलवे कालोनी अजय कुमार घायल हो गए। मुठभेड़ की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक आदित्य लांगे मौके पर पहुंचे गए और मौका मुआयना कर टीम का हौसला बढ़ाया।

पुलिस अभिरक्षा में घायल बदमाशों का जिला अस्पताल में उपचार कराया गया। जिम संचालन की हत्या के बाद से धरपकड़ के लिए पुलिस, स्क्वायड व सर्विलांस की टीम लगाई गई थी। अरविंद हत्याकांड में स्वजन की तहरीर पर मुगलसराय पुलिस ने श्याम सिंह यादव उर्फ कल्लू, ब्रिजेश यादव, काजू यादव, राजू यादव, बाबा यादव उर्फ रामअवध यादव उर्फ घूरे, पंकज यादव, रोहित यादव व ओम प्रकाश यादव सभी निवासी ग्राम सिटिकिया, थाना अलीनगर के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था। घटना में संलिप्त आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन कर दिया गया था।

गुरुवार को मुखबिर से सूचना मिली कि रोहित यादव उर्फ राहुल, प्रियांशु यादव उर्फ काजू यादव और 25-25 हजार रुपये पुरस्कार घोषित बदमाश बृजेश यादव उर्फ बाबा यादव व श्याम सिंह यादव उर्फ कल्लू यादव एमजी मार्ग हाईकोर्ट प्रयागराज पहुंचे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने यहां पहुंचकर आरोपितों को गिरफ्तार किया। घटना में प्रयुक्त असलहा की बरामदगी के लिए आरोपितों को लेकर पुलिस पहुंची। इसी बीच बदमाशों ने पुलिस फायर कर दिया। पुलिस की आत्मरक्षार्थ कार्रवाई में चारों घायल हो गए।

रोहित यादव के पास से एक 32 बोर पिस्टल, प्रियांशु यादव के पास से एक 32 बोर पिस्टल, बृजेश यादव के पास से एक 315 बोर पिस्टल और श्याम सिंह यादव के पास से एक पिस्टल 315 बोर का बरामद हुआ। पूछताछ में बताया कि जमीन विवाद व रुपयों के लेन-देन को लेकर अरविंद की हत्या की गई।

70 लाख का हिसाब न देने पर कर दी हत्या

श्याम यादव उर्फ कल्लू और अरविंद यादव पहले जिगरी दोस्त हुआ करते थे और साथ मिलकर प्रॉपर्टी का काम करते थे। दोनों ने चकिया में 11 बिस्वा जमीन मिलकर एग्रीमेंट करवाई थी। लेकिन, सिकटिया हत्याकांड में कल्लू के जेल चले जाने के बाद अरविंद ने वह जमीन 12 लाख रुपये प्रति बिस्वा की दर से बेच दी। कल्लू ने बताया कि जेल से निकलने के बाद उसने अरविंद से 70 लाख रुपये के हिसाब की मांग की, लेकिन अरविंद ने पैसे देने से इन्कार कर दिया। पहले वह जमानत में खर्च का हवाला देता रहा और बाद में टालमटोल करने लगा। यह विवाद समय के साथ बढ़ता गया और कल्लू ने अपने साथियों के साथ मिलकर अरविंद की हत्या कर दी।

गन्ने के खेत में मिले दुल्हन के कपड़े, ड्रोन उड़ाकर देखा तो... खुला सुहागरात का ये गहरा राज, सदमे में दूल्हा

आर्यावर्त संवाददाता

हमीरपुर। गाजे-बाजे और बारातियों को लेकर दूल्हा अपनी दुल्हनिया के पास पहुंचा। दोनों ने एक दूसरे को सात जन्मों तक साथ रहने का वादा किया। फिर दूल्हा उसे ससुराल ले आया। परिवार बहुत खुश था कि अब उनके घर में नया सदस्य आ गया है। मगर कोई नहीं जानता था कि दुल्हन आगे क्या करने वाली है। दुल्हन ने फिर तीसरे ही दिन ऐसा कांड कर डाला, जिससे दूल्हा और उसका परिवार सदमे में चला गया।

मामला उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले का है। यहां शादी के तीसरे ही दिन नई-नवेली दुल्हन ने रात को बाहर से कुंडी लगाकर खेला कर दिया। सुबह जब ससुराल वालों की आंख खुली तो नजारा देखकर दंग रह गए। घर से दुल्हन गायब थी। बहू रानी को फिर सभी यहां वहां ढूंढने लगे। गांव वाले भी दुल्हन की तलाश में जुट गए। फिर खेतों में जाकर देखा

तो दुल्हन के कपड़े वहां पड़े हुए थे। मगर दुल्हन वहां नहीं थी।

गांव वालों ने ड्रोन उड़ाकर देखा तो कपड़ों के अलावा उन्हें वहां कुछ भी नहीं मिला। फिर सभी का माथा ठनका। उन्होंने घर में देखा कि वहां से सारा कैश और जेवर गायब थे। वो जान गए कि दुल्हन कांड करके चली गई है। फिर उन्होंने थाने में जाकर तहरीर दी।

पुलिस ने बताया- दुल्हन बुधवार की देर रात दरवाजे की कुंडी बाहर से लगाकर फरार हो गई। ससुराल वाले अगले दिन प्रीति भोज की तैयारी में थे क्योंकि लड़के वालों ने बेटे की शादी की रिसेप्शन जो देनी थी। मगर सुबह जब सोकर उठे तब उन्हें दुल्हन लापता मिली। फिर उसे तलाशा गया तो गन्ने के खेत में दुल्हन के कपड़े मिले। करीब दो घंटे तक खेतों में ड्रोन उड़ाकर दुल्हन की खोजबीन की गई, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। फिर पता चला कि घर में रखा सारा कैश और जेवर भी गायब हैं। इससे सारा मामला साफ हो गया। दुल्हन तो लुटेरी निकली।

सीसीटीवी में जाते दिखी दुल्हनिया

बिलरख गांव निवासी दयाराम सैनी ने बताया- कुछ लोगों के बहकावे में आकर उसने 90 हजार रुपये देकर अपने बेटे राहुल सैनी की शादी कानपुर नगर के रेवना की एक महिला से कराई थी। राहुल की शादी से घर वाले खुश थे और गांव वालों को प्रीतिभोज की तैयारी की जा रही थी। मंगलवार की रात दुल्हन दरवाजे के बाहर से कुंडी लगाकर फरार हो गई। सुबह जब परिजन जागे तो दुल्हन के न मिलने पर अफरातफरी मच गई। गांव में चर्चा हुई तो ग्रामीणों का हुजूम लग गया और दुल्हन की तलाश शुरू कर दी गई। इसके लिए ड्रोन का भी सहारा लिया गया। करीब दो घंटे तक ग्रामीण खेतों के ऊपर ड्रोन उड़ाते रहे, मगर दुल्हन का कुछ पता नहीं चला। फिर गांव में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में देर रात दो बजे के आसपास दुल्हन तेजी से अकेले जाते हुए दिखाई दी।

प्रीतिभोज के लिए रखे थे 50 हजार

पीड़ति दयाराम का कहना है कि दुल्हन मंगलसूत्र, बिछिया, पायलें सहित 80 हजार के जेवरात और प्रीतिभोज के लिए रखे 50 हजार रुपए लेकर चंपत हुई है। दयाराम का कहना है कि दुल्हन को भगाने में बिचौलियों की भूमिका है। शादी के पहले कुछ दिन वह उन्हीं के घर रह रही थी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची यूपी 112 पुलिस ने जांच-पड़ताल की। इस संबंध में इंस्पेक्टर रामआसरे सरोज का कहना है कि यूपी 112 में सूचना दी गई थी। पुलिस जांच कर रही है। अभी तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।

ई-रिक्शा चालक सभी प्रपत्रों को पूर्ण करते हुए वाहन चलाए-अलका शुक्ला

सुल्तानपुर। पयागीपुर और अमहट चैराहा, सुल्तानपुर में समस्त ई रिक्शा चालकों को जानकारी दी गई कि वे सभी 31 जुलाई तक अपने वाहनों पर अपना नाम, मोबाइल नम्बर, ड्राइविंग लाइसेंस नम्बर और आधार नम्बर अवश्य लिखवा लें और सभी प्रपत्रों को पूर्ण करते हुए सावधानी पूर्वक वाहन चलाएं। इन स्थानों पर लगने वाले जाम के संदर्भ में भी परिवहन विभाग द्वारा लोगों को जागरूक किया गया। यह कार्यवाही परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस की संयुक्त कार्यवाही द्वारा किया गया। एआरटीओ अलका शुक्ला ने बताया कि ई रिक्शा द्वारा अक्सर जाम लगने की सूचना प्राप्त होती है। ई रिक्शा चालकों का विवरण रिक्शे पर लिखे रहने पर कोई भी दुर्घटना होती है तो इससे उनके संबंध में आसानी से जानकारी प्राप्त हो सकेगी। आम जन मानस भी उनके विवरण को जान सकेगा। वैसे भी राहगीर जिस वाहन पर यात्रा कर रहा है उसे इस तरह के अंकन से संबंधित वाहन और चालक के संबंध में जानकारी प्राप्त हो सकेगी।

मतांतरण के लिए दबाव बनाने का आरोप, 10 लाख रुपये का दे रहे थे लालच

आर्यावर्त संवाददाता

सिद्धार्थनगर। मतांतरण से जुड़ा एक और मामला सामने आया है। एक व्यक्ति आरोप लगाया है कि सदर थाना क्षेत्र के महुवरिया निवासी एक व्यक्ति ने उसे मतांतरण के लिए 10 लाख रुपये का प्रलोभन दिया था।

उसे कलमा पढ़ने के लिए दबाव देने लगा। उसने मना किया तो उसे मारा पीटा। उसने सदर थाने में तहरीर देकर संबंधित व्यक्ति पर कार्रवाई की मांग की है। उसने पुलिस से मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग की है। हालांकि पुलिस का कहना है कि उन्हें इस संबंध में कोई तहरीर नहीं मिली है। सदर थाना क्षेत्र के विजय नगर निवासी वीरेंद्र कुमार ने सदर थाने पर गुरुवार को तहरीर देकर आरोप लगाया है कि महुअरिया के एक व्यक्ति से दो वर्ष पहले उनकी मुलाकात हुई। धीरे-धीरे उनके बीच मेलजोल बढ़ गया।

उन्होंने अपने विद्यालय में उन्हें चपरासी की नौकरी के लिए कहा। साथ ही यह भी कहा कि वह उन्हें नौ हजार रुपये महीने देंगे। वीरेंद्र ने बताया कि वह नौकरी के लिए तैयार हो गए। इस दौरान उन्होंने उन्हें अपने अनूपनगर स्थित मकान पर बुलाया और इस्लाम धर्म अपनाने के लिए कहा। उन्हें 10 लाख रुपये देने का प्रलोभन भी दिया, लेकिन उसने मना कर दिया। इसे लेकर आरोपित ने उन्हें मारा पीटा और गाली देकर भगा दिया। वीरेंद्र ने कहा कि स्कूल संचालक के पास नेपाल की भी नागरिकता है और फर्जी पासपोर्ट बनवाकर कतर भी रहता है। वीरेंद्र ने थाने में तहरीर देकर आरोपित के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है।

इस मामले की कोई जानकारी नहीं है और न ही इस संबंध में कोई तहरीर मिली है। तहरीर मिलने पर मामले की जांच की जाएगी।

दुर्गा प्रसाद, प्रभारी निरीक्षक सदर

यूपी के इस जिले में विलय हुए स्कूलों में नहीं जा रहे बच्चे, इस वजह से बना हुआ भय

आर्यावर्त संवाददाता

पलिगढ़ (मऊ)। शिक्षा क्षेत्र रानीपुर के पयिलवापार प्राथमिक विद्यालय के बच्चे विलय हुए स्कूल में नहीं जा रहे हैं। इस विद्यालय के बच्चों का विलय डेढ़ किमी दूर विद्यालय में किया गया है। इसके कारण छोटे बच्चों द्वारा पैदल चलकर पहुंचना संभव नहीं है।

वहीं कुछ अभिभावकों ने बताया कि दोनों विद्यालय के बीच की तकरीबन एक किमी की दूरी सिवान है। यह सूनसान है। यहां आवारा कुत्ते, जंगली जानवर और घड़रोज के हमले से डर बना रहता है। इसकी वजह से बच्चे सुरक्षित नहीं है।

अभिभावकों का कहना है कि शिक्षा विभाग के स्थानीय अधिकारियों ने न किसी से इस संदर्भ में कोई संवाद किया न बच्चों के दिक्कतों के विषय में सोचा। बिना जमीनी हकीकत देखे व समझे जल्दबाजी में विलय का निर्णय ले आदेश जारी कर दिया गया।

यही हाल दुर्जेपुर प्राथमिक विद्यालय का है। इसका विलय दो किमी से ज्यादा दूरी वाले विद्यालय में कर दिया गया है। खबर लगते ही प्रधान सहित गांव के लोगों ने धरना-प्रदर्शन करने के साथ उच्चाधिकारियों को शिकायती पत्र देना शुरू कर दिया।

नतीजा यह कि बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष कुमार उपाध्याय ने आनन फानन में आदेश को रद्द करते हुए एक बगल के परिषदीय विद्यालय के बच्चों को दुर्जेपुर प्राथमिक विद्यालय में विलय कर दिया।

शिक्षा चैपाल ग्रामीण शिक्षा व्यवस्था के महत्वपूर्ण कदम : शैलेन्द्र प्रताप सिंह

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुल्तानपुर। दूबेपुर के उतरी ग्रामसभा के उच्च प्राथमिक विद्यालय उतरी में शिक्षा चैपाल और अभिभावक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय प्रबंधन समिति, अभिभावकों, शिक्षकों, विद्यार्थियों एवं शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, स्कूल ड्रॉपआउट दर में कमी और सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देना रहा।

मुख्य अतिथि एमएलसी सुलतानपुर/अमेठी शैलेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि शिक्षा चैपाल जैसे प्रयास ग्रामीण शिक्षा व्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं। आपने अभिभावकों को अपने बच्चों का नामांकन परिषदीय विद्यालयों में करवाने हेतु प्रेरित किया।तथा सरकार की शिक्षा के लिये चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं पर चर्चा की। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सुलतानपुर उपेन्द्र गुप्ता ने निपुण भारत मिशन और दिव्यांग बच्चों के लिये चलाई जा रही योजनाओं की चर्चा की और उनको उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की चर्चा की। खण्ड शिक्षा अधिकारी दूबेपुर राम तीरथ वर्मा ने पूरे ब्लॉक के कायाकल्प का डेटा प्रस्तुत किया तथा शिक्षकों द्वारा टीएलएम और आईसीटी के प्रयोग का डेटा प्रस्तुत किया।

बैठक में निम्नलिखित बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं की स्थिति, विद्यार्थियों की उपस्थिति और शैक्षणिक प्रगति अभिभावकों की भागीदारी और जिम्मेदारी शिक्षकों की नियमितता और गुणवत्तासरकारी शैक्षणिक योजनाओं की जानकारी एवं क्रियान्वयन को बताया। सभी उपस्थित प्रतिभागियों ने शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने हेतु सहयोग का संकल्प लिया।

रायबरेली के ऊंचाहार में प्राइवेट पार्ट काटने के बाद युवक को कालोनी में फेंका, देह व्यापार गिरोह पर शक

आर्यावर्त संवाददाता

रायबरेली। ऊंचाहार में गुरुवार देर रात रायबरेली का युवक संदिग्ध परिस्थिति में रेलवे कालोनी में अचेत अवस्था में पड़ा मिला। इस युवक का प्राइवेट पार्ट कटा था और उसके शरीर पर कपड़े नहीं थे।

रेलवे पुलिस बल ने मौके पर पहुंच घायल को सीएचसी पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल से ट्रामा सेंटर लखनऊ रेफर किया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई। चर्चा रही कि युवक क्षेत्र में तेजी से फल फूल रहे देह व्यापार गिरोह का शिकार हो गया है। रायबरेली के निराला नगर के रत्नेश कुमार पुरानी रेलवे कालोनी में संदिग्ध परिस्थिति में पड़े मिले। बताया जा रहा है कि वह किसी कार्य से ऊंचाहार कस्बा आए थे। कालोनी में रात्रि गश्त कर रहे सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें नग्नावस्था में बेहोशी की हालत में जमीन पर पड़ा देखा। इसकी जानकारी होते ही क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई।

प्राइवेट पार्ट का आधा हिस्सा कटने से रक्तस्राव अधिक

सुरक्षाकर्मियों ने आनन-फानन युवक को एंबुलेंस की मदद से सीएचसी पहुंचाया। सीएचसी अधीक्षक डा. मनोज शुक्ल ने बताया कि युवक के प्राइवेट पार्ट का आधा हिस्सा कटने से रक्तस्राव अधिक हो गया है, जिससे उसकी हालत नाजुक बनी है। बेहतर इलाज के लिए उसे जिला अस्पताल भेजा गया है। जहां से ट्रामा सेंटर लखनऊ रेफर किया गया।

कार्यवाहक कोतवाली प्रभारी सियाराम राजपूत ने बताया कि रत्नेश के आसपास मादक पदार्थ के अवशेष पाए गए हैं। वह यहां कैसे पहुंचा, क्या घटना हुई है, इसकी जांच कराई जा रही है। प्रार्थना पत्र मिलने पर केस दर्ज किया जाएगा।

धड़ल्ले से फल फूल रहा देह व्यापार

स्थानीय लोगों का कहना है कि कस्बा से लेकर एनटीपीसी रोड पर कई रेस्टोरेंटों में दिन रात खुलेआम देह व्यापार का व्यवसाय चल रहा है। जिसमें स्थानीय महिलाओं व युवतियों के अतिरिक्त बाहर से भी लड़कियां बुलाई जाती हैं। यहां के इस देह व्यापार के जाल में फंसकर क्षेत्र के युवा बर्बाद हो रहे हैं। यही नहीं बाहर के लोग भी इसके लिए कस्बा आते हैं। लोगों का कहना है कि घायल युवक की स्थिति देख कर तो यही लगता है कि शायद वह भी इसी चक्कर में फंस गया। आरोप है कि शिकायतों के बावजूद स्थानीय प्रशासन इस पर अंकुश लगाने में नाकाम साबित है।

व्यवस्था सुधारें वरना कार्रवाई तय... बिजली की आंख मिचौली से खफा सीएम योगी ने अफसरों को दी चेतावनी

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। बिजली की आंख मिचौली से खफा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को बिजली अधिकारियों को चेतावनी देते हुये कहा कि ट्रिपिंग, ओवरबिलिंग और अनावश्यक कटौती किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं की जाएगी। विद्युत आपूर्ति के लिये व्यवस्था में सुधार करना ही होगा वरना कार्रवाई के लिये तैयार रहें।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां ऊर्जा विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में स्पष्ट शब्दों में कहा कि प्रदेश में बिजली व्यवस्था अब केवल तकनीकी या प्रशासनिक विषय नहीं, बल्कि जनता के भरोसे और शासन की संवेदनशीलता का पैमाना बन चुकी है। बैठक में मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि जून 2025 में उत्तर प्रदेश ने रिकॉर्ड 31,486 मेगावाट की अधिकतम बिजली मांग सफलतापूर्वक पूरी की। इस अवधि में 16,930 मिलियन यूनिट बिजली की आपूर्ति की गई। लगातार बढ़ रही उमस (ह्यूमिडिटी) और तापमान ने खपत को अप्रत्याशित रूप से बढ़ाया, इसके बावजूद शहरी क्षेत्रों में औसतन 24 घंटे, तहसील स्तर पर 21.5 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे तक बिजली उपलब्ध कराई गई।

मुख्यमंत्री ने ट्रिपिंग की लगातार आ रही शिकायतों पर गहरी नाराजगी जताई और निर्देश दिया कि प्रत्येक फीडर की तकनीकी जांच हो, कमजोर स्थानों की पहचान कर तुरंत सुधार कराया जाए। उन्होंने कहा कि जहाँ ज़रूरत हो, वहां ट्रांसफॉर्मरों की क्षमता तुरंत बढ़ाई जाए ताकि ओवरलोडिंग की स्थिति न बने।

उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि फील्ड से प्राप्त वास्तविक शिकायतों का समाधान समयबद्ध ढंग से हो, ताकि जनता को राहत मिले। उन्होंने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों से कहा कि संसाधनों की कोई कमी नहीं है, सरकार ने बिजली उत्पादन, पारेषण और वितरण को मजबूत करने के लिए रिकॉर्ड बजट उपलब्ध कराया है। ऐसे में किसी स्तर पर लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी डिस्कॉम के प्रबंध निदेशकों से उनके क्षेत्रों की आपूर्ति की स्थिति जानने के बाद मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि हर स्तर पर जवाबदेही तय की जाए। बिलिंग व्यवस्था पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हर उपभोक्ता को हर महीने सही समय पर स्पष्ट और सटीक बिल मिलना चाहिए।

फॉल्स या ओवरबिलिंग जैसी शिकायतें जन विश्वास को तोड़ती हैं और विभाग की साख को नुकसान पहुंचाती हैं। यह किसी भी स्थिति में नहीं होना चाहिए। बिलिंग एफिशिएंसी बढ़ाई जाए। उन्हें जानकारी दी गई कि अब तक 31 लाख उपभोक्ता स्मार्ट मीटर से जोड़े जा चुके हैं और इस प्रक्रिया को ब्लॉक स्तर तक ले जाने का कार्य तेजी से जारी है।

योगी ने तकनीकी और वाणिज्यिक हानियों (लाइन लॉस) को चरणबद्ध रूप से नीचे लाने का लक्ष्य तय करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हर डिस्कॉम को अपने स्तर पर ठोस रणनीति बनाकर काम करना होगा। साथ ही, जहां आवश्यक हो, पारेषण व वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया भी गति पकड़े।

बिजली उत्पादन की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री को बताया गया कि राज्य की कुल उत्पादन क्षमता वर्तमान में 11,595 मेगावाट है, जिसमें थर्मल, जल विद्युत, नवीकरणीय और केंद्रीय योजनाओं की परियोजनाएं शामिल हैं। घाटमपुर और मेजा जैसी नई परियोजनाओं के पूरा होने के बाद यह क्षमता अगले दो वर्षों में 16,000 मेगावाट से अधिक हो जाएगी।

मुख्यमंत्री ने इन परियोजनाओं की सतत निगरानी और समयबद्ध पूर्णता सुनिश्चित करने को कहा। कृषि क्षेत्र को लेकर मुख्यमंत्री ने कृषि फीडरों के तेजी से पृथक्करण और किसानों को प्रधानमंत्री कुसुम योजना से जोड़ने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी ट्यूबवेलों को सौर ऊर्जा से जोड़ने का कार्य प्राथमिकता पर होना चाहिए, ताकि किसानों को स्थायी राहत मिल सके और पारंपरिक बिजली पर निर्भरता कम हो। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बिजली व्यवस्था केवल ट्रांसफॉर्मर और वायरिंग नहीं, यह जन अपेक्षा और शासन की प्रतिबद्धता का दर्पण है। हमारा दायित्व है कि हर नागरिक को यह महसूस हो कि उसे बिना भेदभाव, पारदर्शी और समयबद्ध बिजली मिल रही है।

यूपी में 40 जिलों में आईसीयू तैयार, गंभीर मरीजों को सहूलियत, नर्सिंग स्टाफ को भी किया जा रहा प्रशिक्षित

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। प्रदेश में गंभीर रूप से बीमार मरीजों को उनके ही जिले में इंटेसिव केयर यूनिट (आईसीयू) की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। प्रदेशभर के 40 जिला अस्पतालों में आईसीयू को सक्रिय कर दिया गया है। प्रदेश के जिला अस्पतालों में आईसीयू की सुविधा का लगातार विस्तार किया जा रहा है। जिन अस्पतालों में आईसीयू वार्ड नहीं थे, वहा बनाया जा रहा है। अब तक करीब 40 जिलों में आईसीयू बनकर तैयार हो गया है। यहां मरीजों को भर्ती किया जा रहा है। इसके लिए डॉक्टरों के साथ ही नर्सिंग स्टाफ को भी अलग से प्रशिक्षण दिया गया है।

इस विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का नेतृत्व महारानी लक्ष्मी बाई (एमएलबी) मेडिकल कॉलेज, झांसी के प्रोफेसर अंशुल जैन ने किया, जो क्रिटिकल केयर मेडिसिन के प्रसिद्ध विशेषज्ञ हैं। अभी भी जिला अस्पतालों के डॉक्टरों, नर्सों और लैब टेक्नीशियनों सहित स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के विविध समूह को गहन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पाठ्यक्रम में वेंटिलेटर प्रबंधन, रोगी निगरानी, संक्रमण नियंत्रण और आईसीयू देखभाल के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं सहित कई आवश्यक विषय शामिल थे।

इन जिलों में मरीजों को दी जा रही आईसीयू की सुविधा

वर्तमान में राजधानी लखनऊ के कई अस्पतालों में पूरी तरह से चालू और सक्रिय आईसीयू मरीजों की सेवा कर रहे हैं। इनमें बलरामपुर अस्पताल, सिविल अस्पताल, रानी लक्ष्मीबाई अस्पताल, लोकबंधु अस्पताल और राम सागर मिश्रा अस्पताल शामिल हैं, जो शहर के निवासियों को महत्वपूर्ण गहन देखभाल सेवाएं प्रदान करते हैं। इसके अलावा बाराबंकी, अयोध्या, सीतापुर, उन्नाव, कानपुर नगर, वाराणसी, प्रयागराज, अंबेडकर नगर, बलिया, आजमगढ़, मऊ, गोरखपुर और बस्ती के जिला अस्पतालों में भी आईसीयू प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं। इसी तरह इटावा, बांदा, चित्रकूट, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, अलीगढ़, बुलंदशहर, कन्नौज, झांसी, बरेली, मुरादाबाद, मेरठ, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर और शामली के जिला अस्पतालों में सक्रिय आईसीयू आवश्यक देखभाल प्रदान कर रहे हैं।

लोकबंधु अस्पताल के आईसीयू प्रभारी डॉ. दीपक कुमार मौर्य ने बताया कि उनके 11 बेड वाले आईसीयू ने पिछले महीने ही 150 से अधिक मरीजों का सफलतापूर्वक इलाज किया है। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षित कर्मचारी अब वेंटिलेटर और अन्य अत्याधुनिक उपकरणों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने में सक्षम हैं, जिससे वे गंभीर रूप से बीमार मरीजों को सर्वोत्तम देखभाल प्रदान कर पा रहे हैं।

चंडीगढ़-लखनऊ सुपरफास्ट में टीटीई ने यात्री को पीटा, ग्वालियर-बरौनी में बुजुर्गों से की बदसलूकी

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। ट्रेनों में टीटीई की मनमानी बढ़ती जा रही है। चंडीगढ़-लखनऊ सुपरफास्ट में टीटीई ने यात्री को पीट दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वहीं, ग्वालियर-बरौनी एक्सप्रेस में टीटीई ने बुजुर्गों से बदसलूकी की, जिसकी शिकायत डीआरएम से की गई है।

गाड़ी संख्या 12232 चंडीगढ़-लखनऊ सुपरफास्ट का है। चंडीगढ़ से लखनऊ आ रहे पैसेंजर कृष्णा चतुर्वेदी ने बताया कि थर्ड एसी इकॉनमी क्लास एम-1 में टीटीई ने एक यात्री की पिटाई कर दी। दोनों के बीच टिकट को लेकर कुछ विवाद हुआ था।

उन्होंने मामले का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया एक्स पर साझा किया है, जिसके बाद मामले की जांच के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि, वीडियो में टीटीई द्वारा यात्री की पिटाई नजर नहीं आ रही है, लेकिन यात्रियों का कहना है कि टीटीई ने पैसेंजर को पीटा है।

इसी क्रम में निशांत ने शिकायत दर्ज कराई कि गाड़ी संख्या 11123 ग्वालियर बरौनी मेल में उनके दादा-दादी यात्रा कर रहे थे। उनकी उम्र 75 वर्ष के आसपास की है। उनका पीएनआर 2338671142 था। खलीलाबाद स्टेशन के पास टीटीई ने उनसे बदसलूकी की। ऐसे में डीआरएम से टीटीई के खिलाफ जांच की मांग की गई है।

इंस्पेक्टर गोमतीनगर विस्तार सुधीर अवस्थी ने बताया कि शाम

नशे में धुत दंपती और युवती का सड़क पर हंगामा, तीनों शांतिभंग के आरोप में गिरफ्तार किया

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। जनेश्वर मिश्र पार्क के पास बृहस्पतिवार शाम कार सवार दंपती व एक युवती ने शराब के नशे में जमकर हंगामा किया। पुलिस ने समझाने का प्रयास किया, पर वे नहीं माने। तीनों को शांतिभंग में गिरफ्तार करते हुए कार सीज कर दी गई है।

पांच बजे जनेश्वर पार्क के पास कार सवार बाराबंकी निवासी प्रॉपर्टी डीलर व कैब चालक मनोज वर्मा, उसकी पत्नी वर्षा और महिला मित्र सुनीता वर्मा शराब के नशे में हंगामा कर रहे थे। लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने समझाने की कोशिश की तो तीनों उग्र हो गए और मोबाइल फोन निकालकर पुलिसवालों पर हफ्ता वसूलने का आरोप लगाते हुए वीडियो बनाने लगे। हंगामा देख भीड़ लग गई। पुलिस ने तीनों को शांत करने का प्रयास किया, पर वे बात सुनने के लिए राजी नहीं हुए। आखिरकार तीनों को शांतिभंग के आरोप में गिरफ्तार करते हुए मनोज की कार सीज कर दी गई। इंस्पेक्टर ने बताया कि आरोपी भरवारा इलाके में रहते हैं। दंपती व युवती के हंगामे व पुलिस से अभद्रता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है।

प्राइवेट गाड़ी टैक्सी में चला रहा था मनोज

इंस्पेक्टर ने बताया कि मनोज ने पूछताछ में बताया कि वह प्रॉपर्टी डीलिंग के साथ अपनी कार टैक्सी में चलता है। गाड़ी की नंबर प्लेट कॉमर्शियल नहीं थी। इस कारण उसकी गाड़ी को सीज किया गया। इंस्पेक्टर ने बताया कि ब्रेथ एनालाइजर से जांच में तीनों के शराब पीने की पुष्टि हुई है।

महिला ने पति पर लगाया मारपीट के साथ ही दूसरी करने का आरोप

लखनऊ। गोसाईगंज क्षेत्र के रनमऊ स्थित ससुराल की रहने वाली एक महिला ने अपने पति पर दूसरी शादी करने व उसके साथ मारपीट करने की शिकायत पुलिस से की है।

अहिबन्नापुर अलीगंज की रहने वाली अपशाना के अनुसार उसकी शादी 2009 में गोसाईगंज क्षेत्र के गांव रनमऊके निवासी महताब उर्फ शेरा के साथ हुई है।पीड़िता का आरोप है कि पत्नी बच्चे होते हुए उसके पति ने दूसरी शादी कर ली है। इसी वजह से वह उसकी व बच्चो की देखभाल नही करता है।वह महिला बच्चो को पालने के लिए नौकरी करती है तो पति नौकरी भी छोड़वा देता है।वही 22 जुलाई को आरोपित पति ने पीड़िता पत्नी को गालियां देते हुए उसकी पिटाई कर दी और जान से मारने की धमकी दी।जिसकी लिखित शिकायत पीड़िता ने गोसाईगंज पुलिस से की है।जिसपर पुलिस मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है।

चाय पीने के लिए रुके ट्रक वाले को दबंगों ने पीटा

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। सुशांत गोल्फ सिटी क्षेत्र में किसान पथ पर पासिन ढकवा गांव के पास चाय पीने के लिए रुके ट्रक वाले को दबंगो ने जमकर पीटा। इन्दलपुर जुबराज कानपुर नगर थाना चौबेपुर के रहने वाले

करन गौतम पुत्र श्रीकृष्ण निवासी के अनुसार वह 23 जुलाई को ट्रक में कबरई से डस्ट लेकर किसान पथ होते हुए श्रावस्ती जा रहा था।इसी बीच रात लगभग 11 बजे पासिन ढकवा गांव के पास स्थित तिराहे पर चाय पीने के लिए रुका था।तभी वहां मौजूद कुछ लोग उससे अभद्रता करते हुए गाली गलौज करने लगे।पीड़ित ने जब इसका विरोध किया तो उन लोगों ने उसकी पिटाई कर दी और जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए।पीड़ित के अनुसार मार पीट के दौरान आरोपित एक दूसरे का आपस में नाम ले रहे थे जिससे उनकी पहचान अरविन्द अजय सुनील व प्रवेश निवासीगण पासिन ढकवा के रूप में हुई है।पीड़ित ने मामले की लिखित शिकायत सुशांत गोल्फ सिटी पुलिस से की है।जिसपर पुलिस मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है।सूत्रों की मानें तो उस तिराहे पर कई लोगों ने अवैध रूप से दुकानें लगा रखी है।जिससे वहां पर लगभग हर समय दबंगो का जमावड़ा रहता है।जिसके चलते वहां पर अक्सर इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं।लोगों का कहना है कि यदि जिम्मेदारों ने कोई ध्यान न दिया तो वहां पर कभी कोई बड़ी घटना भी हो सकती है।

झमाझम बारिश के साथ प्रदेश में मानसून हुआ सक्रिय, अगले तीन-चार दिनों तक जारी रहेगा बारिश का दौर

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। बंगाल की खाड़ी में बृहस्पतिवार की शाम को विकसित हुए कम दबाव के क्षेत्र के असर से उत्तर प्रदेश में मानसून की वापसी देखने को मिली है। शुक्रवार को प्रदेश के दक्षिणी और पूर्वी जिलों सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया आदि में अच्छी बारिश हुई।

बारिश के दौरान इन इलाकों में 30 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलीं। मौसम विभाग की ओर से शनिवार को दक्षिणी यूपी और बुंदेलखंड समेत कुल 14 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। साथ ही 43 जिलों में गरज चमक के साथ वज्रपात की आशंका जताई गई है। प्रदेश के विभिन्न इलाकों में बारिश का दौर अगले तीन-चार दिनों तक जारी रहेगा।

शुक्रवार की शाम तक प्रयागराज में सर्वाधिक 58.8 मिमी बारिश हुई। इसके बाद बस्ती में 53 मिमी, विंध्य क्षेत्र के चुर्क में 37.2 मिमी, अमेठी में 29 मिमी, कानपुर में 13.2 मिमी, बाराबंकी में 12 मिमी, बहराइच में 11.8 मिमी बारिश दर्ज की गई।

आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया की बंगाल की खाड़ी में विकसित हुए कम दबाव के असर से अगले दो-तीन दिन प्रदेश के दक्षिणी-पूर्वी हिस्से में अच्छी बारिश के आसार हैं।

यहां भारी बारिश की संभावना

बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, आगरा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर और आसपास के इलाकों में।

इन जिलों में बिजली गिरने की आशंका

बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, गाजीपुर, मऊ, बलिया, लखीमपुर खीरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, सहारनपुर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बदायूं, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर व आसपास के इलाकों में।

मणिपर्वत मेले के साथ कल शुरू होगा झूलनोत्सव, प्रवाहित होगी गीत, संगीत व अध्यात्म की त्रिवेणी

लखनऊ। सावन की हरियाली के साथ रामनगरी में भक्ति और परंपरा का ऐतिहासिक संगम होने जा रहा है। 27 जुलाई से मणिपर्वत मेले के साथ झूलनोत्सव का शुभारंभ होगा, जो रक्षाबंधन तक चलेगा। एक पखवाड़े तक अयोध्या के हर मठ, मंदिर और गली में भक्ति, संगीत और अध्यात्म की त्रिवेणी प्रवाहित होगी। रामनगरी में झूलनोत्सव का श्रीगणेश मणिपर्वत मेले के दिन से ही होता है। इस दिन रामनगरी के प्रमुख मंदिरों से भगवान के विग्रह के रथ पर सवार कर भव्य शोभायात्रा निकाली जाती है। फिर यह शोभायात्रा मणिपर्वत पर पहुंचती है। वहां भगवान के विग्रह को मणिपर्वत पर स्थित मंदिर में दर्शन कराया जाता है। उसके बाद परिसर में स्थित विशालकाय बरगद के वृक्ष पर पड़े झूले पर सभी मंदिरों के विग्रह को झुलाया जाता है। मान्यता है कि भगवान राम माता सीता के साथ सावन महीने में तृतीया तिथि के दिन यहां झूला झूलते थे।

भारतीय नारियों ने हमें सशक्त राष्ट्र की धरोहर सौंपी है : आनन्द द्विवेदी

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। भारतीय इतिहास में नारी सशक्तिकरण की मिसाल, धर्म ध्वजा संवाहिका और कुशल शासिका के रूप में पुण्यश्लोका अहिल्याबाई होलकर का नाम सदैव आदर के साथ लिया जायेगा। जिन्होंने न्याय, धर्म और जनकल्याण को सर्वोपरि रखते हुए एक ऐसे सशक्त राष्ट्र की आधारशिला रखी जिससे हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। यह उद्गार थे पवन सिंह चौहान, विधान परिषद् सदस्य के जो अहिल्याबाई होल्कर पर केन्द्रित एक आयोजन में अतिथि के रूप में बोल रहे थे।

कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भाजपा महानगर अध्यक्ष श्री आनन्द द्विवेदी ने कहा कि महारानी अहिल्याबाई होलकर भारतीय संस्कृति की मूर्तिमान प्रतीक थीं। उनके समक्ष कितने आपत्ति तथा कसौटियों के प्रसंग आए, लेकिन उन्होंने सबका बड़े धैर्य से मुकाबला कर धर्म ध्वजा संभालते हुए देश को सदैव सुरक्षित रखा। कार्यक्रम अहिल्याबाई होलकर की 300 वीं जयंती के अवसर पर वाइब्रेंट फोक आर्ट एंड कल्चर सोसाइटी तथा संस्कृति विभाग, उ.प्र. द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था जिसमें संजय गुप्ता, व्यापार मंडल, पद्मा गिडवानी वरिष्ठ गायिका, ब्रह्मदेव, अशोक सिंह, यू. पी सिंह, संस्कृति विभाग के पूर्व अधिकारी कमलेश पाठक और शैलेन्द्र अनेक गणमान्य अतिथि की उपस्थिति रही।

शिक्षामित्रों ने मनाया काला दिवस, जिला मुख्यालयों पर एकत्र होकर मानदेय बढ़ाने की उठाई मांग

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षामित्रों ने शुक्रवार को पूरे प्रदेश में काला दिवस मनाया। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के बैनर तले शिक्षामित्रों ने जिला मुख्यालयों पर एकत्र होकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन भेजा। इसके माध्यम से मानदेय बढ़ाने आदि की मांग की।

25 जुलाई 2017 को शिक्षामित्रों का समायोजन निरस्त किया गया था। इसके बाद से शिक्षामित्र हर साल 25 जुलाई को काला दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को विभिन्न जिलों में मुख्यालयों पर एकत्र होकर मृत शिक्षामित्रों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही सीएम को भेजे ज्ञापन में मूल विद्यालय से वंचित शिक्षामित्रों को मूल विद्यालय, उनकी ग्राम पंचायत में समायोजित करने, महिला शिक्षामित्रों को विवाह के बाद उनके ससुराल के विद्यालय में समायोजित करने के शासनादेश का जल्द

अनुपालन करने की मांग उठाई।

संघ के प्रदेश मंत्री कौशल कुमार सिंह ने बताया कि इसके साथ ही शिक्षामित्रों को ईपीएफ योजना में शामिल करने, उनको आयुष्मान भारत योजना में शामिल करके मेडिकल सुविधा देने, मृत शिक्षामित्रों के परिवार को आर्थिक सहायता देने, उनके परिवार के एक सदस्य को उसी पद पर नियुक्त करने, सेवामुक्त हो रहे शिक्षामित्रों को सरकारी सहायता देने की भी मांग की गई।

जनता के लिए खुशखबरी : बिजली दर पर सुनवाई पूरी, चौतरफा विरोध से दरों में बढ़ोतरी की संभावना कम

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में बिजली दर पर शुक्रवार को सुनवाई पूरी हो गई है। निगमों की सुनवाई की तरह ही राज्य सलाहकार समिति की बैठकों में भी बिजली दर बढ़ाने का चौतरफा विरोध हुआ। विद्युत उपभोक्ता परिषद, मेट्रो कॉर्पोरेशन के साथ ही समिति के अन्य सदस्यों ने भी विरोध किया। हालांकि कॉर्पोरेशन प्रबंधन यह दुहाई देता रहा कि सुधार के लिए दर बढ़ाना जरूरी है, लेकिन नियामक आयोग का मूड उपभोक्ताओं के पक्ष में नजर आया। ऐसे में बिजली दर में बढ़ोतरी की संभावना कम की लग रही है।

पॉवर कॉर्पोरेशन ने विभिन्न निगमों के वार्षिक राजस्व आवश्यकता प्रस्ताव दाखिल किया। करीब 19 हजार करोड़ का घाटा दिखाते हुए लगभग 45 फीसदी बिजली दर बढ़ाने का प्रस्ताव दिया। नियामक आयोग ने विभिन्न निगमों में

सुनवाई की। हर जगह बिजली दर बढ़ाने और निजीकरण प्रस्ताव का विरोध हुआ। शुक्रवार को विद्युत नियामक आयोग अध्यक्ष अरविंद कुमार की अध्यक्षता में ऊर्जा क्षेत्र की राज्य सलाहकार समिति की बैठक हुई। इसमें आयोग की तरफ से निदेशक टैरिफ सरबजीत सिंह ने समूचे विवरण पर प्रस्तुतीकरण किया।

कॉर्पोरेशन प्रबंधन की ओर से कहा गया कि कॉर्पोरेशन के सामने दो ही विकल्प हैं। एक तो सरकार अनुदान दे और दूसरा बिजली दर बढ़ाई जाए क्योंकि पिछले पांच साल से बिजली दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर पर होने वाला खर्च निकालना जरूरी है। इसका उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि नोएडा पॉवर कंपनी का प्रयोग पूरी तरह से फेल है। सामान्य उपभोक्ता परेशान हैं। ऐसे में स्मार्ट प्रीपेड मीटर का खर्च किसी भी कीमत पर उपभोक्ताओं पर नहीं डाला जा सकता है। इससे भी खास बात यह है कि निगमों पर उपभोक्ताओं का करीब 33122 करोड़ रुपये बकाया हैं। इसे बिजली दर में शामिल करते हुए धीरे- धीरे लौटाया जाए।

इससे बिजली दर भी कम हो जाएगी और उपभोक्ताओं का रुपया भी वापस आ जाएगा। इसी तरह मेट्रो कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक सुशील कुमार ने भी बिजली दरों में बढ़ोतरी का विरोध किया। उन्होंने कहा कि मेट्रो को कोई भी सब्सिडी नहीं मिलती है। यदि उसकी दरों में बढ़ोतरी हुई तो मेट्रो कॉरपोरेशन बंदी के कगार पर पहुंच जाएगा। इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने भी बिजली दर बढ़ोतरी का खुलकर विरोध किया। बैठक में आयोग के सदस्य संजय कुमार सिंह, ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव नरेंद्र भूषण, पावर कार्पोरेशन के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार, मध्यांचल की प्रबंध निदेशक रिया केजरीवाल सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

तीन सदस्यों ने लिखित में दिया प्रस्ताव

बैठक में उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा, दीपा और डॉ भारत राज सिंह ने लिखित प्रस्ताव में कहा कि 33122 करोड़ के बकाये के एवज में 45 फीसदी बिजली दर कम की जाए। केंद्र सरकार आरडीएसएस स्कीम में 44094 करोड़ खर्च कर रही है। ऐसे में दक्षिणांचल व पूर्वांचल को आत्मनिर्भर बनाया जाए। उसका निजीकरण किसी भी कीमत पर न किया जाए। उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि जब पॉवर कॉर्पोरेशन ने 18885 करोड़ का टेंडर 27342 करोड़ में दिया है तो फिर अतिरिक्त खर्च का भार उपभोक्ताओं पर क्यों डाला जाए। उन्होंने मांग की कि घरेलू उपभोक्ताओं की बीपीएल श्रेणी की दरें 3 से 4 रुपये प्रति यूनिट प्रस्तावित की गई हैं, जो भाजपा के संकल्प पत्र के खिलाफ है।

तकनीक बन रही है जनकल्याण का माध्यम

एक बात साफ हो जानी चाहिए कि तकनीक मात्र उपकरण बनें तो यह मानवता के हित में नहीं हो सकती। ऐसे में तकनीक को जनकल्याण का माध्यम बनाना होगा। डिजिटल युग में बहुत कुछ बदला है। हमारे सोच का तरीका बदला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में आज सामान्य मानव मन से भी अधिक तेजी से तकनीक काम करने लगी है। तकनीक ने इतना विकास कर लिया है कि अब मशीनें सोचने लगी है। हमारे चिंतन और मनन को प्रभावित करने लगी है। इसमें कोई दो राय नहीं कि तकनीक ने जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रवेश करने के साथ सहज बनाया है। समय तो यहां तक बदल गया है कि अब पढ़ना-लिखना ही नहीं तकनीक ने सोचना और निकश तक पहुंचना आरंभ कर दिया है। यह विकास का उजला पक्ष होने के साथ ही इसके पीछे छुपा काला पक्ष भी गंभीर है। हांलाकि प्रकृति अपना काम कर रही है और वह लगातार हमें चेतावनी देती जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) हमारे जीवन का हिस्सा बन चुकी है। वह हमारे निर्णयों को प्रभावित कर रही है, हमारी प्राथमिकताएं तय कर रही है, और हमारी सोच को प्रभावित कर रही है। इस दौर में हमें ऐसे नेतृत्व की जरूरत है जो तकनीक के चमत्कारों को संवेदनशीलता और दूरदृष्टि के साथ दिशा दे।

एआई एक्शन समिट में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सटीक और सामयिक टिप्पणी की है। दरअसल "टेक्नोलॉजी का लोकतंत्रीकरण होना चाहिए। हमें जन-केंद्रित एप्लिकेशन बनाने चाहिए। साथ ही हमें साइबर सुरक्षा, दुष्प्रचार और डीपफेक जैसी चुनौतियों का समाधान भी करना होगा।" डिजिटल नवाचार का उपयोग अब पारदर्शिता, सहभागिता और संवेदनशील सेवा-प्रणाली के रूप में सामने आ रहा है। हमारा देश आज एआई और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की मजबूत नींव रख रहा है। 2024 में केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित इण्डिया एआई मिशन इसका जीता जागता उदाहरण है। इस मिशन के तहत 10,300 करोड़ रु. के निवेश से देश में एक विश्वस्तरीय एआई कंप्यूटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है 18,693 जीपीयू से लैस साझा कंप्यूटिंग क्षमता विकसित कर भारत को वैश्विक एआई शक्तियों की अग्रिम पंक्ति में खड़ा करना है। विशेषज्ञों को मानना है कि यह सिस्टम ओपन-सोर्स एआई मॉडल डीपसीक से 9 गुना अधिक सक्षम होगा और चैटजीपीटी जैसी प्रणालियों की दो-तिहाई शक्ति तक पहुंचेगा। यानी यह केवल तकनीकी उपलब्धि नहीं होगी अपितु डिजिटल क्षेत्र में भारत को आत्मसम्मान व दुनिया के देशों की अग्रणी पंक्ति में खड़ा करने की घोषणा है।

दरअसल तकनीक का उपयोग मानव कल्याण के उद्देश्य से होना चाहिए। सरकारें इस बात को समझती है और यही कारण है कि ई-गवर्नेंस से लेकर डिजिटल शिक्षा, एआई आधारित स्वास्थ्य सेवाओं और नागरिक सुविधा केंद्रों तक हर नीति के केंद्र में आम आदमी है, सिस्टम नहीं। राज्यों में तकनीक को 'डिजिटल एक्सेस' के बजाय 'डिजिटल एम्पावरमेंट' के रूप में उपयोग किया जाने लगा है। और यही बदलाव राज्यों को एक सॉफ्ट-टेक्नोलॉजिकल स्टेट बना रहा है। राज्यों में चल रहे हरित अभियान, जल संरक्षण योजनाएं, सौर ऊर्जा प्रोत्साहन और ईको-टूरिज्म और इसी तरह की अन्य पहल इस सोच के साथ धरातल पर उतर रही हैं। यहां तक कि मानसिक स्वास्थ्य अभियान, डिजिटल डिटॉक्स क्लासेस और संस्कार संवाद जैसे कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। ताकि युवा स्मार्टफोन के स्क्रीन से आगे सोच सकें और अपनी जड़ों से जुड़े रहें।

आज सवाल यह नहीं कि हमें तकनीक से डरना चाहिए या नहीं, बल्कि यह है कि हम तकनीक को किस नैतिक दायरे में संचालित कर सकते हैं। केन्द्र के साथ ही राज्यों की सरकारें इसे समझने लगी है और यह कारण है कि राज्यों द्वारा तकनीक का उपयोग भविष्य की संभावनाओं और जनकल्याण नीतियों के रुप में सामने आ रहा है।

आकंठ तक भ्रष्टाचार में डूबी कांग्रेस किस-किस की पैरवी करेगी

अपने जीजाजी की पैरवी करने से पहले राहुल गांधी शायद यह भूल गए कि सोनिया गांधी और खुद उन पर भी भ्रष्टाचार के गंभीर मामले चल रहे हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर कर चुकी है।

योगेंद्र योगी

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शुरुआती चार्जशीट दायर करने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर वाड्रा को जानबूझ कर परेशान करने का आरोप लगाया। भ्रष्टाचार के मामलों में कांग्रेस की हालत इतनी दयनीय हो चुकी है कि राहुल के इस आरोप के चंद दिनों बाद ही ईडी ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल को कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने भूपेश बघेल के आवास सहित कई स्थानों पर छापेमारी की और महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए। यह घोटाला 2019-2022 के दौरान लगभग 2161 करोड़ रुपए की अवैध वसूली से जुड़ा है। सवाल यह है कि राहुल, सोनिया और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आखिरकार किस-किस कांग्रेस के नेता के भ्रष्टाचार के लिए केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों को दुर्भावना की कार्रवाई के लिए जिम्मेदार ठहराएंगे।

ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शुरुआती चार्जशीट दायर की। इस मामले में ईडी की तरफ से 11 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इस मामले पर लोकसभा नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मेरे जीजाजी को पिछले 10 सालों से इस सरकार की तरफ से परेशान किया जा रहा है। यह आरोपपत्र है, उसी षडयंत्र का ही एक और हिस्सा हैं। रॉबर्ड वाड्रा के खिलाफ ये चार्जशीट शिखोपुर लैंड डील मामले में पेश की गई है। ईडी के मुताबिक वाड्रा ने यहां 3.53 एकड़ महज 7.5 करोड़ रुपये में खरीदी थी, जिसे कुछ ही समय बाद वाड्रा ने 58 करोड़ रुपये में बेच दिया था।

अपने जीजाजी की पैरवी करने से पहले राहुल गांधी शायद यह भूल गए कि सोनिया गांधी और खुद उन पर भी भ्रष्टाचार के गंभीर मामले चल रहे हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर कर चुकी है। नेशनल हेराल्ड मामला कांग्रेस के शासनकाल में शुरू हुआ था। ईडी की चार्जशीट में सोनिया गांधी आरोपी नंबर 1 और राहुल गांधी आरोपी नंबर 2 हैं। आरोप पत्र में कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा और सुमन दुबे को भी मामले में आरोपी बनाया गया है। राहुल गांधी को वाड्रा के मामले में साजिश नजर आती है। लेकिन दूसरे घोटालों के मामलों में कांग्रेस भ्रष्टाचार के मामलों में की चुप्पी

साबित करती है कि कांग्रेस अपने अतीत को दोहरा रही है।

केंद्र में कांग्रेस की सरकार नहीं हैं, लेकिन जिन गिने-चुने राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, वहां से भ्रष्टाचार की सूचनाएं आती रहती हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने कोलार-चिक्काबल्लापुर जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड (कोमूल) की 2023 भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं के संबंध में कर्नाटक कांग्रेस विधायक केवाई नानजेगौड़ा की 1.32 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। कोलार जिले के मालूर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले नानजेगौड़ा, कोमुल के अध्यक्ष भी हैं। ईडी के अनुसार कोमुल द्वारा आयोजित भर्ती प्रक्रिया में एक लिखित परीक्षा और एक साक्षात्कार शामिल था, लेकिन पैसे और राजनीतिक सिफारिशों के बदले में इसमें हेरफेर किया गया था। संघीय एजेंसी ने आरोप लगाया कि नांजेगौड़ा की अध्यक्षता वाली भर्ती समिति ने कोमूल के प्रबंध निदेशक के.एन. गोपाल मूर्ति के साथ मिलकर अन्य निदेशकों के साथ मिलकर कुछ कम योग्य उम्मीदवारों को लाभ पहुंचाया, जबकि योग्य उम्मीदवारों को वंचित रखा।

कांग्रेस की हालत यह हो गई कि वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष तक भ्रष्टाचार के आरोपों के घेरे में रहे हैं। कर्नाटक में खड़गे के बेटे राहुल खड़गे के नेतृत्व वाले सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट को आवंटिक एक जमीन में हेरफेर का आरोप लगाया गया था। कर्नाटक में यदि भाजपा की सरकार होती तो खड़गे के खिलाफ भी भ्रष्टाचार का मामला दर्ज हो जाता। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने संदिग्ध परिस्थितियों में खड़गे के परिवार द्वारा संचालित सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट को 5 एकड़ जमीन आवंटित थी। दिलचस्प बात यह है कि 5 एकड़ जमीन (खड़गे परिवार द्वारा चलाए जा रहे ट्रस्ट को) इलाके में अनुसंधान एवं विकास सुविधाओं के लिए नियम तैयार करने के कुछ दिनों भीतर दी गई थी। इस मामले का खुलासा होने के बाद खड़गे बैकफुट पर आ गए थे। खड़गे परिवार के स्वामित्व वाले सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट ने विवादास्पद स्थल को वापस करके भ्रष्टाचार से मुक्त होने का प्रयास किया।

कांग्रेस जिन भी राज्यों में सत्ता में रही है, उनमें से ऐसा एक भी राज्य नहीं जिनमें मुख्यमंत्री और मंत्रियों पर भ्रष्टाचार-घोटालों के आरोप नहीं लगे हों। भ्रष्टाचार के मामलों को देखें तो दिल्ली से लेकर हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक के बड़े कांग्रेस नेता सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी जैसी एजेंसियों के निशाने पर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस अपने नेताओं पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों से इनकार करती है। पार्टी का कहना है कि बीजेपी की मोदी सरकार राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है।

सर्वाधिक आश्चर्य की बात यह है कि कांग्रेस में गांधी परिवार खड़गे सहित अन्य नेता भाजपा पर दुर्भावना से कार्रवाई का आरोप लगाते रहे हैं, किन्तु अदालतों में चल रहे इनके खिलाफ मामलों में यह दुर्भावना अभी तक साबित नहीं कर सके। चर्चित घोटालों और घपलों में अदालतों से किसी को क्लीन चिट नहीं मिल सकी। सवाल यह भी है कि आखिर कांग्रेस का दामन इतना ही पाक साफ है तो ईडी और अन्य एजेंसियों के आरोपों को अदालतों से मुक्ति क्यों नहीं मिल सकी। कांग्रेस सहित 14 राजनीतिक दलों को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग की याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार कर दिया था।

शीर्ष कोर्ट ने कहा था कि नेताओं को विशेष इम्यूनिटी नहीं दी जा सकती। नेताओं के भी आम नागरिकों जैसे अधिकार हैं। अगर सामान्य गाइडलाइन जारी की तो ये खतरनाक प्रस्ताव होगा। नेताओं की गिरफ्तारी पर अलग से गाइडलाइन नहीं हो सकती। इस टिप्पणी के बाद यह याचिका वापस ले ली गई। निरन्तर भ्रष्टाचार के आरोपों को झेल रही कांग्रेस और विपक्षी दलों को यह बात शायद अभी तक समझ नहीं आई कि जब तक भ्रष्टाचार पर जीरा टॉलरेंस की नीति नहीं अपनाएंगे, तब तक देश के मतदाताओं से खोया हुआ विश्वास फिर से हासिल नहीं कर पाएंगे।

अजब-गजब

चचेरी बहन से ही इश्क कर बैठी 18 साल की लड़की, बोली- आनिया मेरी लवर है

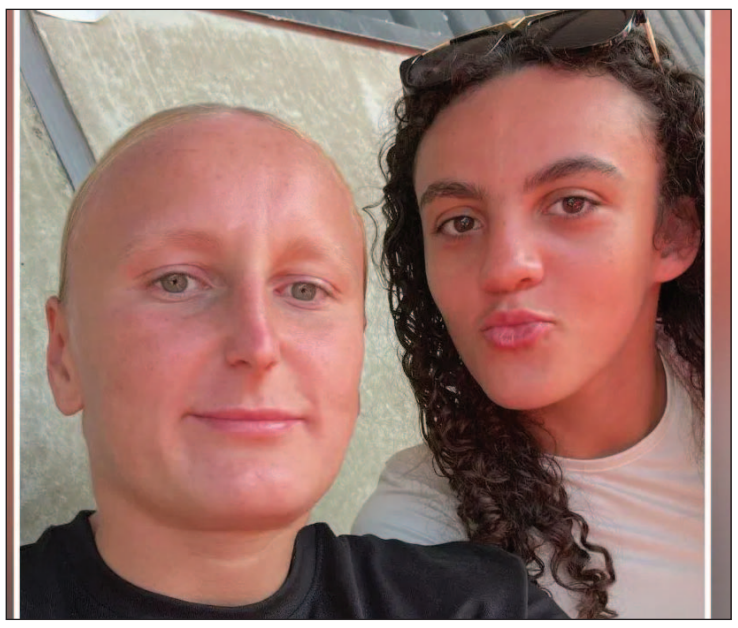

एक कहावत है 'लव इज़ ब्लाइंड', लेकिन इतना भी क्या अंधा कि रिश्तों की मर्यादा भी न देखे? हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसी ही अजीब लव स्टोरी (Ajab Gajab Love Story) ने बवाल मचा दिया है, जिसने सदियों पुरानी कहावत को नया अर्थ दे दिया है। लोग क्या कहेंगेइसकी परवाह किए बिना दो लड़कियों ने सिर्फ प्यार को चुना है। लेकिन इस प्रेम कहानी में ट्विस्ट यह है कि दोनों ही लड़कियां आपस में चचेरी बहनें हैं।

चौंकाने वाला यह मामला इंग्लैंड के ग्रिम्सबी का है। जहां की 18 वर्षीय फाज ने टिकटॉक पर खुलासा किया कि वह अपनी 24 वर्षीय चचेरी बहन आनिया के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप में है। फाज ने आनिया के साथ अपनी तीन तस्वीरें भी शेयर की हैं।

द सन की एक रिपोर्ट के अनुसार, कपल ने एक वायरल ट्रेंड में हिस्सा लिया था, जिसमें लोगों को यह बताना था कि वे कितने समय से रिलेशनशिप में हैं या एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं। लेकिन फाज और आनिया के जवाब ने इंटरनेट पर तूफान ला दिया। कपल ने कहा, केवल दो महीने। हमें ये रिश्ता छिपाकर रखना पड़ा, क्योंकि हम आपस में कजिन हैं।

इस अनोखे खुलासे के साथ फाज ने एक वीडियो क्लिप शेयर कर कैप्शन दिया, जैसा कि कहा जाता है कि घर की बात घर में ही रखें। फाज ने आनिया को अपना 'लवर' बताते हुए #RelationshipGoals जैसे हैशटैग का भी इस्तेमाल किया। ये भी देखें:पिता की उम्र के शख्स को दिल दे बैठी 19 साल की लड़की, रचा ली शादी, बोली- उसके बिना अधूरी हूं कपल का यह वीडियो इंटरनेट पर आग की तरह फैल गया, और नेटिजन्स ने उनकी पोस्ट पर कमेंट्स की बौछार कर दी। कुछ लोगों ने इसे 'प्यार की अभिव्यक्ति' करार दिया, तो अधिकांश यूजर्स ने उनके रिलेशनशिप को भद्दा बताया है।

हालांकि, फाज और आनिया लोगों की ओर से मिल रहे नेगेटिव कमेंट्स से बेपरवाह नजर आ रही हैं। इस अनोखे कपल का मानना है कि उनका रिश्ता सच्चा है और समाज की दकियानूसी सोच से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता।

ब्लॉग

मुंबई लोकल ट्रेन बम धमाकों का फैसला और उठते सवाल

ललित गर्ग

11 जुलाई 2006 को मुंबई की भीड़भरी लोकल ट्रेनों में हुए सीरियल बम धमाकों ने समूचे देश को झकझोर कर रख दिया था। पीडित परिवारों के साथ-साथ जन-जन को आहत किया था। 7 जगहों पर हुए इन धमाकों में 187 निर्दोष लोगों की जान गई और 824 से ज्यादा लोग घायल हुए। यह भारत के सबसे बड़े आतंकी हमलों में से एक था। लेकिन इन बम धमाके को लेकर सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया, कोर्ट ने विशेष मकोका अदालत की ओर से 12 अभियुक्तों को दी गई सजा को गैरकानूनी करार दिया। इन सभी आरोपियों का बरी हो जाना सवाल के साथ-साथ चिन्ता भी पैदा करता है। इसीलिये करीब 19 साल बाद आए अदालत के इस फैसले को लेकर न केवल कानूनी दायरे में, बल्कि सामाजिक व नैतिक दृष्टिकोण से भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद सवाल वहीं घूमकर आ जाता है कि इतने बड़े नुकसान का दोषी कौन है?

लम्बी न्यायिक प्रक्रिया एवं जांच के बाद 2015 में मुंबई की विशेष मकोका अदालत ने 12 अभियुक्तों को दोषी करार दिया, जिसमें से 5 को फांसी और 7 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। यह फैसला लगभग 8 वर्षों की सुनवाई, 250 से ज्यादा गवाहों और हजारों पन्नों की गवाही के बाद आया। लेकिन 2023 और फिर 2025 में कुछ सिविल सोसाइटी संगठनों, मानवाधिकार समूहों और कुछ कानूनी विशेषज्ञों ने फैसले पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कुछ दोषियों को पर्याप्त सबूतों के बिना फंसाया गया, पुलिस की जांच पक्षपातपूर्ण रही और कई जगह कानून के दायरे का अतिक्रमण किया गया। इसी को आधार बनाकर हाईकोर्ट में जिस तरह से एक-एक करके सारे सबूतों की धज्जियां उड़ायी, उससे पूरे सिस्टम को लेकर संदेह उठता है। जब इतने अहम मामले में इतनी लचर एवं लापरवाहीपूर्ण जांच हुई, तो फिर दूसरे तमाम केस में क्या होता होगा? गवाहों के बयान दर्ज करने से लेकर सबूत जुटाने तक, हर जगह लापरवाही एवं कौताही बरती गई।

कानून की दृष्टि में अपराध केवल घटना नहीं, उस घटना के पीछे की मंशा, सबूतों की पुष्टि, प्रक्रिया की शुद्धता और निष्पक्षता का भी मूल्यांकन करता है। "दोषी को सजा मिलनी चाहिए"-यह एक सार्वभौमिक सिद्धांत है, लेकिन "निर्दोष को दंड न मिले"- यह उससे भी अधिक महत्वपूर्ण नैतिक सिद्धांत है। भारतीय दंड संहिता, मकोका और गैरकानूनी गतिविधियाँ रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) जैसे सख्त कानून आतंकवाद से निपटने के लिए बनाए गए, लेकिन इनका उपयोग अक्सर राजनीतिक प्रभाव, मीडिया ट्रायल, या जनभावनाओं को शांत करने के लिए किया गया है। ट्रेनों में हुए सीरियल बम धमाकों के मामले में अनेक ज्वलंत सवाल खड़े हुए हैं कि क्या सभी

दोषियों को वास्तव में पर्याप्त प्रमाणों के आधार पर दोषी ठहराया गया है? यदि नहीं, तो यह न्याय व्यवस्था के लिए एक गंभीर प्रश्न है। क्या पुलिस या जांच एजेंसियों ने निष्पक्ष जांच की? कई बार जांच एजेंसियों पर 'नतीजे पहले, जांच बाद में' का आरोप लगा है। क्या विशेष अदालतों का गठन निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करता है या त्वरित दंड की नीति अपनाता है? क्या कानून केवल सख्ती का पर्याय बन गया है या उसमें मानवीय संवेदना का स्थान है? क्या मीडिया ट्रायल ने वास्तविक न्याय को प्रभावित किया? इन प्रश्नों के उत्तर मिलना ही चाहिए।

देश के सामने आतंकवाद के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की चुनौती है, तो वहीं न्याय की नैतिकता बनाए रखने की भी जिम्मेदारी है। अगर कानून का इस्तेमाल अन्याय के लिए किया गया, तो आतंकवाद के खिलाफ जंग की नैतिकता ही सवालों में पड़ जाएगी। न्याय केवल प्रतिशोध नहीं, बल्कि नैतिक और विधिसम्मत संतुलन का नाम है। जो निर्दोष है, उसे दोषमुक्त करना और जो दोषी है, उसे यथोचित दंड देना- यही कानून का आदर्श उद्देश्य है। मुंबई बम धमाके जैसी वीभत्स घटनाएं देश के लिए चुनौती हैं, लेकिन इन चुनौतियों से निपटने के नाम पर अगर हम न्याय और कानून के मूलभूत सिद्धांतों से समझौता करते हैं, तो हम एक असुरक्षित और अन्यायपूर्ण समाज की नींव रखेंगे। आवश्यक है कि न्याय केवल न्यायालयों की प्रक्रिया न रहे, वह जनविश्वास का प्रतीक बने।

एक बड़ा सवाल है कि न्याय व्यवस्था पर भरोसा कैसे बना रहे? इसके लिये जरूरी है कि जांच प्रक्रिया पारदर्शी हो, आरोपों की पुष्टि डिजिटल और वैज्ञानिक सबूतों से हो। अदालतें किसी दबाव, राजनीतिक प्रभाव या जनभावना से परे निर्णय लें। न्याय में देरी भी अन्याय है, लेकिन जल्दबाजी में न्याय भी गलत निर्णय की आशंका बढ़ाता है। सभी मामलों में उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय में स्वतंत्र और निष्पक्ष पुनरावलोकन की व्यवस्था रहे। निचली अदालते हो या सर्वोच्च अदालते- न्यायिक फैसलों का बदलना न्यायिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता एवं निष्पक्षता के लिये गंभीर चुनौती है। ऐसे अनेक मामले हैं जिनमें निचली अदालतों में दिये गये मौत की सजा को ऊपरी अदालतों ने बदल दिया। जांच में खामियों, गवाही में कमी और कमजोर सबूतों के चलते ऊपर की अदालतों में केस खारिज होते हुए बार-बार देखे गये हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने हाल में एक आरोपी की मौत की सजा को खारिज करते हुए कहा कि 'जब दांव पर इंसानी जिंदगी लगी हो और उसकी कीमत खून हो, तो मामले को पूरी ईमानदारी से देखा जाना चाहिए।' दुर्भाग्य से मुंबई की लोकल ट्रेनों में हुए सीरियल बम ब्लास्ट की जांच में इस भावना का सही से पालन नहीं किया गया। इस मामले में सभी आरोपियों का बरी हो जाना न केवल न्याय प्रक्रिया पर बल्कि जांच एजेंसियों पर सवाल पैदा करता है। प्रश्न है कि अगर 12 लोग निर्दोष थे तो इतने बरसों तक आतंकी होने का दाग लिए जिल्लत की जिंदगी क्यों जीते रहे? अगर ये दोषी थे तो जांच इतनी कमजोर क्यों हुई? यह केस निचली अदालतों के कामकाज के तरीकों पर भी बड़ा सवालिया निशान है। सबूतों को लेकर इतने संदेह थे, लेकिन निचली अदालत ने उन पर गौर नहीं किया। यह विडम्बनापूर्ण एवं हमारी न्याय प्रक्रिया की विसंगति ही है।

यह पहला मामला नहीं, जहां जांच में खामियों, गवाही में कमी और कमजोर सबूतों के चलते ऊपर की अदालतों में केस खारिज हो गया हो। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते तीन लोगों की मौत की सजा रद्द करते हुए उन्हें हत्या के आरोपों से बरी कर दिया था। पिछले ही हफ्ते सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने भी 2011 में हुई दोहरी हत्या और रेप के आरोपी को छोड़ने का आदेश दिया। शीर्ष अदालत ने जांच में गंभीर कमियां गिनाई थीं। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया था कि झूठे मुकदमों की वजह से जिन्हें लंबा समय जेल में बिताना पड़ा है, उन्हें मुआवजा देने के लिए कानून बनाने पर विचार करना चाहिए। अब मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट केस को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। महाराष्ट्र सरकार लोकल ट्रेन बम धमाके में आरोपियों को निर्दोष छोड़ने के बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए अपील दायर की है। देश उम्मीद करता है कि इस बार तथ्यों को सही ढंग से रखा जाएगा। यह केवल एक केस नहीं, न्याय व्यवस्था पर आम लोगों के यकीन का मामला है।

भारत में न्याय प्रणाली पर आम धारणा है कि पुलिस और अदालतें लोगों की जिंदगी को तबाह कर देती हैं, वर्षों लम्बी न्याय प्रक्रिया झेलने के बाद भी लोगों को समुचित न्याय नहीं मिल पाता है। न्याय में देरी न्याय के सिद्धांत से विमुखता है, न्याय प्राप्त करना और इसे समय से प्राप्त करना किसी भी आदर्श न्याय व्यवस्था में आम व्यक्ति का नैसर्गिक अधिकार होता है। न्याय सिर्फ होना ही नहीं चाहिये बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिये।

मेरठ पुलिस ने 6 साल बाद सुधारी अपनी गलती, छांगुर के गुर्गे बदर सिद्दीकी पर एफआईआर

आर्यावर्त संवाददाता

मेरठ। छांगुर बाबा के गिरफ्तार होने के बाद उसकी गैंग के सदस्यों पर पुलिस अब नकेल कसती जा रही है। पुलिस ने अब साल 2019 के एक मामले में छांगुर बाबा गैंग के सदस्य बदर सिद्दीकी के खिलाफ FIR दर्ज की है। बदर पर हिंदू युवती को किडनैप करने का आरोप लगा था। पहले पुलिस ने इस केस में कोई FIR दर्ज नहीं की थी। मगर 6 साल बाद अब मेरठ की सिविल लाइन पुलिस ने मेरठ के रहने वाले बदर और उसके पिता के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

इन पर हिन्दू युवतियों का धर्मांतरण करने का आरोप है। पीड़ित परिवार ने मेरठ के पुलिस कप्तान डॉक्टर विपिन तारा से मुलाकात कर सारी जानकारी दी थी। इस मामले में तत्कालीन सिविल लाइन थाना प्रभारी

अब्दुल रहमान सिद्दीकी पर जांच बैठी थी, जिसके बाद अब्दुल रहमान सिद्दीकी को सस्पेंड कर दिया गया है। पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के बाद मेरठ के कप्तान ने मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए थे। इसके बाद सिविल लाइन थाने में बदर और उसके पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इन पर आरोप है कि इन्होंने हिंदू युवतियों को बरगला कर धर्म परिवर्तन कराया है।

क्या-क्या लिखा है FIR में?

बदर सिद्दीकी के खिलाफ दर्ज हुए मुकदमे में लिखा गया है कि जिस हिंदू लड़की का धर्म परिवर्तन बदर ने कराया था, उससे निकाह भी कर लिया था। उस युवती के भाई ने बताया कि बदर ने उसकी बहन के साथ मार पिटाई भी की थी। बदर के संपर्क में कई हिंदू लड़कियां थीं, जिसमें से अब तक दो युवती का मेरठ में पता चल सका है। ऐसा माना जा रहा है कि इसके अलावा भी कई युवतियां बदर के संपर्क में थी, जिनका धर्म परिवर्तन कराया गया होगा।

नोएडा का मामला बताकर टाला

इस मामले में फिलहाल जांच शुरू की गई है। माना जा रहा है कि कार्रवाई का दायरा बढ़ सकता है और आंच नोएडा पुलिस तक भी पहुंच सकती है। छांगुर बाबा के गुर्गे बदर अख्तर सिद्दीकी पर पांडवनगर निवासी सुनीता (बदला हुआ नाम) के अपहरण और धर्मांतरण का आरोप लगा था। सुनीता साल 2019 में लापता हो गई थी। परिजनों ने उसकी काफी खोजबीन की। बाद में थाने जाकर सुनीता के भाई ने तत्कालीन इंस्पेक्टर सिविल लाइन मेरठ अब्दुल रहमान सिद्दीकी को घटना की जानकारी दी। मगर उस समय मुकदमा दर्ज नहीं किया गया और नोएडा का घटनास्थल बताकर टरका दिया था, इसके बाद नोएडा में भी सुनवाई नहीं हुई।

बम्हनपुर में भंडारे का आयोजन, कांवरियों का भव्य स्वागत

आर्यावर्त संवाददाता

निघासन-खीरी। विकासखंड निघासन की ग्राम पंचायत बम्हनपुर में शुक्रवार को कांवड़ यात्रा की वापसी पर भंडारे का आयोजन किया गया। 22 जुलाई को रवाना हुई कांवड़ यात्रा के समापन उपरांत 25 जुलाई को बाजार छावनी क्षेत्र में भंडारा संपन्न हुआ,जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामवासियों ने सहभागिता की।

इस अवसर पर ग्राम प्रधान शशि शुक्ला, ग्राम प्रधान पति संतोष शुक्ला, पूर्व प्रधान सतीश सक्सेना, मुकेश, पुनीत, पवन, राजेश, विवेक, दिनेश, राज, अवध, असलम, शिवा सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। सभी ने भंडारे में सेवा कार्यों में भाग लिया और श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण किया गया।

कांवड़ यात्रा की वापसी पर गुरुवार रात को गांव में भक्ति गीतों के साथ गुलाल खेला गया। महिलाओं व बच्चों ने कांवरियों का जोरदार स्वागत किया। संपूर्ण गांव में श्रद्धा, उत्साह और भक्ति का वातावरण देखने को मिला। गाँववासियों ने इस आयोजन को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई और सामाजिक समरसता का परिचय दिया।

20KG चांदी और करोड़ों का सोना... डिलीवरी बॉय बनकर आए और दिनदहाड़े कर गए ज्वेलरी शॉप में कांड

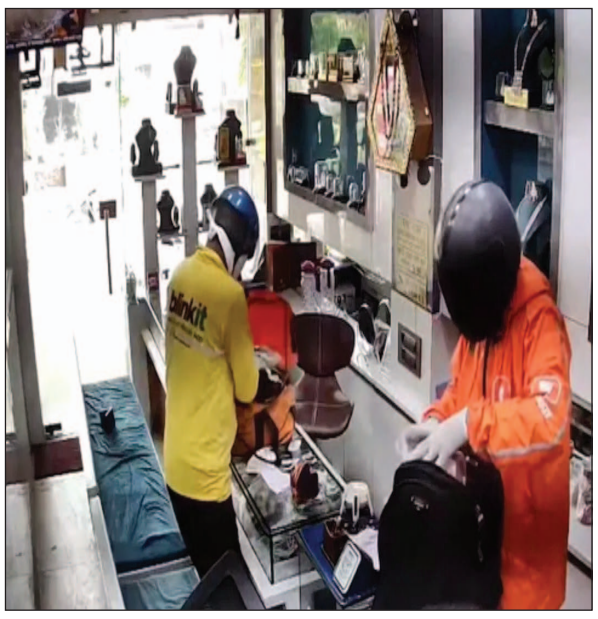

आर्यावर्त संवाददाता

गाजियाबाद। वो एक-एक कर बैग में गहने रख रहे थे, उन्हें रोकने की कोशिश की तो टीशर्ट ऊपर कर पैंट में खोंसी हुई बंदूकें दिखाने लगे। गालियां देने लगे। धमकाने लगे... यह बताते-बताते दुकान का कर्मचारी कांपने लगा। उसकी आंखों में दहशत थी। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के बृज विहार स्थित मानसी ज्वेलर्स की दुकान में दिनदहाड़े लूट की घटना से लोगों में दहशत कायम हो गया है। गुरुवार को हथियारों से लैश दो बदमाशों ने दुकान में लूट को अंजाम दिया। दोनों बदमाश सोने और चांदी के लाखों के गहने लेकर फरार हो गए। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है।

यह घटना करीब 3:30 बजे हुई, जब दुकान मालिक टॉयलेट के लिए बाहर गए हुए थे। अंदर उनके बेटे शुभम वर्मा और एक नौकर मौजूद थे। तभी दो बदमाश दुकान में आए। दोनों ने जो टीशर्ट पहन रखी थी, उसपर स्विग्गी और ब्लिंकिट लिखा हुआ था। दोनों बदमाशों ने पहले नौकर को धक्का दिया, फिर पिस्तौल दिखाकर सभी को डराया और गहनों को बैग में भरने लगे। बदमाश करीब 20 किलो चांदी, 125 ग्राम सोना और 20,000 रुपये कैश लेकर फरार हो गए।

सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई लूट की घटना

वारदात ज्वेलरी शॉप में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे दोनों लुटेरे तेजी से वारदात को अंजाम देकर निकल जाते हैं। वीडियो में दोनों बदमाश गहने बैग में रखते हुए नजर आते हैं। वहीं, एक बदमाश गाली देता नजर आता है। घटना की सूचना मिलते ही लिंक रोड थाना पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी।

जल्द ही लुटेरे पुलिस की गिरफ्त में होंगे- डीसीपी

घटना की पुष्टि करते हुए ट्रांस हिंडन ज़ोन के डीसीपी निमिष पाटिल ने बताया कि पुलिस को वारदात की सूचना शाम करीब 4 बजे मिली, जिसके बाद तत्काल पुलिस टीम मौके पर पहुंची। डीसीपी ने बताया कि दुकान और आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पीड़ितों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं और लुटेरों की पहचान कर उन्हें जल्द गिरफ्तार करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लुटेरों को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा और पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा।

गोली मारने से घायल बालक ने तोड़ा दम

जौनपुर। जिले के शाहगंज में एक मामूली कहासुनी ने एक परिवार की खुशियां छीन ली। 10 वर्षीय अयान को 18 जुलाई को गोली मार दी गई थी। छह दिन तक वाराणसी के अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करने के बाद उसने दम तोड़ दिया।घटना उसरहटा गांव निवासी अफजल के बेटे अयान के साथ हुई। वह अपने मामा अतिकुर्रहमान के साथ मिल्लत नगर अपने ननिहाल आया था। 18 जुलाई को वह मोहल्ले के फैजान के घर गया था। वहां अरंद गांव निवासी आदिल अपने साथियों के साथ मौजूद था। किसी बात पर कहासुनी हो गई और गुस्से में आदिल ने अयान पर गोली चला दी। गोली लगते ही अयान लहूलुहान होकर गिर पड़ा। मोहल्ले में अफरा-तफरी मच गई। परिजन तुरंत मौके पर पहुंचे।घायल अयान को पहले शाहगंज अस्पताल लाया गया। वहां से उसे गंभीर हालत में वाराणसी रेफर कर दिया गया। वाराणसी के अस्पताल में अयान को आईसीयू में रखा गया था।

शादी के एक महीने बाद ससुराल में दामाद का तांडव, दो एंबुलेंस में 20 लोगों को लेकर पहुंचा, गांव वालों पर बोला हमला, 10 घायल

आर्यावर्त संवाददाता

बाराबंकी। उत्तरप्रदेश के बाराबंकी के रसौली गांव में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब लखनऊ से आई दो एंबुलेंस और एक निजी वैन में सवार होकर करीब 20 से 25 युवक गांव में उतर पड़े और जमकर तांडव मचाया। बताया जा रहा है कि हमला करने वालों का नेतृत्व गांव का एक दामाद कर रहा था, जो शादी के महज एक महीने बाद ससुराल में पहुंचा था। हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एंबुलेंस गांव के भीतर खड़ी दिख रही हैं और दोनों पक्षों के बीच जबरदस्त मारपीट होती नज़र आ रही है।

गांव के चश्मदीदों के अनुसार एंबुलेंस और वैन जैसे वाहन देखकर पहले तो लोग समझ नहीं पाए कि क्या हुआ है। कुछ ही देर में इन गाड़ियों से उतरे युवकों ने लाठी-डंडों, लोहे की चैन और धारदार

हथियारों से हमला बोल दिया। दोनों पक्षों से करीब 10 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इनमें 6 की हालत नाजुक बनी हुई है।

गाड़ी तेज चलाने पर की थी कहासुनी

गंभीर रूप से घायल 32 वर्षीय नईमा बानो ने बताया कि उसने 20 जून 2025 को अपनी बेटी जोया की शादी लखनऊ के दुबग्गा थाना क्षेत्र निवासी मोहम्मद दानिश से की थी। बताया जा रहा लखनऊ निवासी दानिश गांव की गली में तेज गाड़ी लेकर अक्सर निकलता था। गांव की गलियों से तेज रफ्तार गाड़ी निकालने पर ग्रामीण टोकते थे। इसको लेकर पूर्व में कहासुनी हुई थी।

गांव के घायल ज़ुबैर ने बताया कि तेज गाड़ी चलाने पर बुधवार को विवाद हुआ था, जिस पर डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंच कर मामला शांत कर दिया था। दूसरे दिन गुरुवार को दानिश तीन एंबुलेंस और एक वैन में 20-25 लोगों को भरकर लाया। सभी के हाथ में डंडे, लाठी, लोहे की चैन और धारदार हथियार थे। उसने आते ही कहा, देखता हूं कौन रोकता है और मारपीट शुरू कर दी। घटना के दौरान बीच-बचाव करने वाले ग्रामीणों को भी बेरहमी से पीटा गया। ज़ुबेर ने बताया की शादी के बाद से ही मोहम्मद दानिश अक्सर गांव की गलियों में तेज़ रफ्तार से गाड़ी दौड़ाता था, जिससे ग्रामीणों में रोष था। कई बार उसे टोका भी गया लेकिन वह धमकी देता रहा कि देखता हूं कौन रोकता है।

दामाद ने लागए आरोप

जिला अस्पताल में भर्ती दानिश ने अपने ऊपर हमला होने की बात कही। उसका आरोप है कि गांव के युवक उसकी साली और अन्य बहनों के साथ रास्ते में छेड़छाड़ करते थे। जब वह दोस्तों के साथ उन्हें समझाने आया तो गांववालों ने ही उस पर हमला कर दिया।

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है जिसमें दो एंबुलेंस और एक वैन गांव के बीच खड़ी दिख रही हैं, और लाठी-डंडों से लैस लोग मारपीट करते नजर आ रहे हैं। पीड़ित पक्ष ने पूरे घटनाक्रम को पूर्व नियोजित साजिश करार देते हुए हत्या के प्रयास, बलवा और गंभीर धाराओं में तहरीर दी है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले में आगे की कार्रवाई जारी है।

जांच मे जुटी पुलिस

बाराबंकी जिले में एक दामाद दो एंबुलेंस और वैन से 20 से ज्यादा साथियों को लेकर ससुराल गुंडई करने पहुंचा। इस दौरान दामाद और गांव वालों के बीच झड़प हुई जिसमें 10 लोग घालय हुए। घटना का वीडियो वायरल है। पुलिस ने कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

तलवार लेकर आया और पत्नी का काट डाला गला, बांदा में क्यों कातिल बना पति?

आर्यावर्त संवाददाता

बांदा। उत्तर प्रदेश के बांदा से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां एक पति ने अपनी पत्नी की तलवार से गला काटकर बेरहमी से हत्या। यह खौफनाक घटना पैलानी की है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आरोपी पति का नाम बजरंगी प्रजापति है।

आरोपी पति बजरंगी प्रजापति अपनी पत्नी शोभा के चरित्र पर शक करता था। इसी शक के चलते पति-पत्नी के बीच अक्सर झगड़े होते थे। शोभा के परिजन का आरोप है कि बजरंगी नशे का आदी था और वह अक्सर पत्नी को लाठी-डंडों से पीटता था। आरोप है कि शोभा ने कई बार पुलिस से शिकायत की, लेकिन समय रहते कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इससे आरोपी के मन से कानून का डर निकल गया था।

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

पुलिस उपाधीक्षक (पैलानी सर्कल) ने बताया कि बजरंगी प्रजापति ने अफेयर के शक में पत्नी की हत्या की है। पुलिस ने आरोपी को वारदात में इस्तेमाल किए गए हथियार समेत गिरफ्तार कर लिया है। फॉरेंसिक टीम ने मौके से खून के नमूने और अन्य साक्ष्य जुटाए हैं। डॉग स्क्वायड की मदद से आरोपी तक पहुंचने में पुलिस को कामयाबी मिली, क्योंकि वह मुंबई भागने की फिराक में था। पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल ने बताया कि पति-पत्नी के बीच लंबे समय से तनाव था और दोनों अलग-अलग रह रहे थे। शक और नशे में डूबे आरोपी ने पत्नी पर कई वार कर हत्या की और फरार होने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने समय रहते उसे दबोच लिया।

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज बांदा भेज दिया है। यह घटना कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है कि आरोपी के खिलाफ समय पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। इस घटना के बाद घरवाले सदमे में हैं। परिजन का रो-रोकर बुरा हाल है।

पांव धोई नदी के खुद उखड़े 'पांव', अगल-बगल दीवारें टूटीं, सड़क पर बहता है पानी

आर्यावर्त संवाददाता

सहारनपुर। शहर के बीचों-बीच से निकलने वाली पांव धोई नदी के किनारे पर बनी दीवार पिछले लंबे समय से कई जगह से बिल्कुल टूट चुकी है। दीवार टूटने की वजह से बारिश के समय पानी पांव धोई नदी से बाहर निकलकर सड़कों पर आ जाता है, जिससे पांव धोई नदी के किनारे की दोनों सड़कों पर जलभराव हो जाता है। इसके अलावा पांव धोई नदी के आसपास कुछ स्पॉट ऐसे हैं, जहां इन टूटी दीवारों की वजह से कई बार बाइक सवार नदी में गिर चुके हैं, जिन्हें स्थानीय लोगों ने बड़ी मुश्किल से बचाया है।

हालांकि सहारनपुर नगर निगम इन टूटी दीवारों को बनवा भी रहा है, लेकिन काम धीमी गति से चलने के कारण लोगों में नगर निगम के प्रति गहरी नाराजगी देखने को मिल रही है। लोग चाहते हैं कि नगर निगम जल्दी ही इन टूटी दीवारों को दुरुस्त करवाए, ताकि उनको हो रही समस्या से निजात मिले।

धोभीघाट से पुल खुमरान तक पांव धोई नदी का एक लंबा हिस्सा है, उसकी दीवार कई जगह से कई कई फीट तक टूटी हुई है। बारिश के दिनों में जब पांव धोई नदी अपने उफान पर आती है तो नदी के टूटे हुए हिस्से की वजह से पानी बाहर सड़क तक आ जाता है, जिससे नदी और सड़क में अंतर तक नहीं दिखता। इसके चलते नदी के दोनों तरफ की सड़क पर कई फीट तक पानी भर जाता है।

नदी के दोनों साइड की सड़कों से रोजाना बड़े-छोटे वाहन गुजरते हैं। जलभराव के चलते सड़क से गुजरने वाले लोगों के साथ आसपास के मोहल्ले के लोगों को भारी परेशानी उठनी पड़ती है। कुछ दिन पहले भारी बारिश के बाद इस नदी में उफान आया था और पानी सड़कों पर निकलकर बहने लगा था। लोग जान जोखिम में डालकर सड़क पार करने को मजबूर थे।

कई बाइक सवार नदी में गिर चुके

नदी की टूटी दीवार की वजह से कई बार हादसे भी हो चुके हैं। गौशाला रोड की तरफ से जो रास्ता पांव धोई नदी की तरफ से होते हुए अग्रवाल धर्मशाल की तरफ जा रहा है, वहां पर एक घूम है और इस घूम की भी दीवार कई फीट तक टूटी पड़ी है। इसी साइड कई बार बाइक सवार नदी में गिर भी चुके हैं, जिनको स्थानीय लोगों ने बड़ी मुश्किल से बचाया है। लोगों में नगर निगम को लेकर नाराजगी थी, जिसके बाद टूटी दीवार के कुछ हिस्सों के पास लकड़ी की बल्लियां लगाई गई थीं। साथ ही नगर निगम ने जल्दी ही इन टूटी जगहों को दुरुस्त करने का दम भरा था।

सिर्फ एक-दो जगह बनाई गई टूटी दीवार

लोगों की इस समस्या को देखते हुए नगर निगम ने पांव धोई नदी की टूटी दीवारों को बनवाने का काम शुरू तो किया, लेकिन वो काम पिछले कुछ समय से धीमी गति से चल रहा है। एक-दो जगह तो नदी के किनारे की टूटी दीवार बना दी गई है, लेकिन जहां दुर्घटना की संभावना ज्यादा है, वहां तक अभी काम नहीं पहुंचा है। काम धीमी गति से चलने के कारण लोग अपनी नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं। नगर निगम के अधिकारियों का कहना है की नदी के किनारों को ठीक करने का काम जल्दी पूरा किया जाएगा। लोगों को जो समस्याएं हो रही हैं, उनको जल्द दूर कर दिया जाएगा।

पांव धोई नदी का क्या है मान्यता?

पांव धोई नदी सहारनपुर शहर से होकर बहने वाली एक नदी है, जिसे कुछ लोग गंगा नदी का स्वरूप मानते हैं।

चोरी करने घर में घुसे थे पति-पत्नी, रस्सी से बांधकर भीड़ ने पीटा, जेवर-कैश बरामद

आर्यावर्त संवाददाता

मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के कोतवाली नगर क्षेत्र में एक सनसनीखेज चोरी की घटना सामने आई है। जीएमडी रोड स्थित एक मकान में चोरी करते समय एक युवक और युवती को लोगों ने रंगे हाथ पकड़ लिया। गुस्साई भीड़ ने दोनों को रस्सी से बांधकर सड़क पर बेरहमी से पीटा। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह उन्हें भीड़ से छुड़ाया और हिरासत में ले लिया। पूछताछ में पता चला कि दोनों आरोपी पति-पत्नी हैं, जो संगठित तरीके से चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे।

जानकारी के अनुसार, अर्पना नामक महिला पहले उसी मकान में झाड़ू-पोंछा करने का काम कर चुकी थी। इस दौरान उसने घर की रेकी कर ली थी। सोमवार को जब

मकान मालिक संजय राजपूत अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने गए हुए थे, तब अर्पना अपने पति दीपक उर्फ गग्गा के साथ घर में घुस गई।

मोहल्ले वालों ने दोनों को पकड़ा

लेकिन घर के अंदर मौजूद महिलाओं ने जब शोर मचाया तो मोहल्ले वालों ने दोनों को पकड़ लिया। इसके बाद उन्हें रस्सी से बांधकर सड़क पर पीटा गया। युवक बुरी तरह लहूलुहान हो गया, जबकि महिला को भी गंभीर चोटें आईं। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें महिला बार-बार हाथ जोड़कर वीडियो न बनाने की गुहार लगाते दिखाई दे रही है।

लाखों के जेवर और कैश बरामद

कोतवाली पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें उन्होंने चोरी की बात स्वीकार की। तलाशी के दौरान पुलिस ने उनके पास से एक जोड़ी सोने के झुमके, तीन अंगूठियां, मांगटीका, लॉकेट, ₹5000 नकद, मोबाइल फोन, स्टील के बर्तन और अन्य घरेलू सामान बरामद किया है।

पुलिस ने दोनों के खिलाफ कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज किया है। उनके खिलाफ मुकदमा संख्या 72/2025 के तहत धारा 305/317(2) बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट में केस दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने में जुटी है कि इस दंपती ने और किन स्थानों पर चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है। घटना के बाद इलाके में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है।

संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत

जौनपुर। जिले के रामपुर थाना क्षेत्र के बंजारी गांव में बीती रात संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता ने टीनशेड में लगे बल्ली के कड़ी में फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना का वीडियो बनाते हुए शव को फांसी से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके बाद मायके से पहुंचे महिला परिजनों ने जमालापुर चौकी पर पहुंचकर घंटों हंगामा किया। किसी तरह समझाने को जाने के बाद भी महिलाएं पुलिस चौकी पर बैठी रही। बताया जा रहा है कि जमालापुर चौकी क्षेत्र के बंजारी मनापुर गांव में गौतम सरोज की पत्नी रूबीना सरोज बीती रात खाना खाने के बाद पति-पत्नी एवं बच्चे अलग-अलग खाट पर टिनसेड के अंदर बने घर में सो गए। रात करीब 3 बजे पति गौतम सरोज को पेशाब लगी तो वह उठा तो पत्नी टिनशेड में लगे बल्ली में पीली साड़ी से फांसी से लटक रही थी। इसके बाद शोरगुल मचाने के बाद आसपास के लोग भी जुटे।

हर दिन फाउंडेशन लगाना पड़ सकता है भारी, स्किन को होते हैं ये 5 बड़े नुकसान

सही से मेकअप करने से न सिर्फ चेहरा खूबसूरत बनता है बल्कि इस कारण आत्मविश्वास भी बढ़ता है। इसी वजह से आज के समय में न सिर्फ महिलाएं बल्कि पुरुष भी प्रतिदिन मेकअप का इस्तेमाल करते हैं। इससे चेहरे की कमियां छिप जाती हैं और चेहरा खिल जाता है।

मेकअप के अहम प्रोडक्ट्स की बात करें तो फाउंडेशन को सबसे खास माना है। इसे लोग अपनी-अपनी स्किन टोन के हिसाब से खरीदते हैं। ये चेहरे पर अच्छा बेस तैयार करता है। पर, क्या आप जानते हैं कि यही फाउंडेशन आपके चेहरे को काफी हद तक नुकसान पहुंचा सकता है।

जी हां, फाउंडेशन मेकअप का जरूरी हिस्सा है, लेकिन इसे लंबे समय तक और रोज़ाना इस्तेमाल करने से त्वचा को कुछ नुकसान हो सकता है। खासकर अगर आप गलत प्रोडक्ट या बिना स्किन केयर के इस्तेमाल करें। आइए आपको भी इस बारे में जानकारी देते हैं।

पोर्स होंगे ब्लॉक

अगर आप प्रतिदिन चेहरे पर फाउंडेशन का इस्तेमाल करते हैं तो इससे स्किन के पोर्स धीरे-धीरे बंद होने लगते हैं। जिसकी वजह से स्किन पर पिंपल्स और ब्लैकहेड्स हो सकते हैं। कई बार तो इसकी वजह मुंहासों की समस्या काफी ज्यादा बढ़ भी जाती है, जो काफी दिक्कत देती है।

एलर्जी और रैशेज

यदि आप सस्ते और लोकल फाउंडेशन का इस्तेमाल हर दिन अपने चेहरे पर कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि कुछ फाउंडेशन में मौजूद केमिकल्स से एलर्जी, खुजली या रैश हो सकते हैं। ये दिक्कत सबसे ज्यादा उन लोगों को होती है, जिनकी त्वचा संवेदनशील त्वचा वालों को होता है।

स्किन का संतुलन बिगड़ेगा

सस्ता फाउंडेशन हर दिन इस्तेमाल कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि इसकी वजह से स्किन की नमी कम हो सकती है। कई मामलों में देखा गया है कि ज्यादा फाउंडेशन के इस्तेमाल से स्किन पर अतिरिक्त तेल भी जमने लगता है, जो आगे जाकर मुंहासों का कारण बनता है।

त्वचा की प्राकृतिक चमक कम होना

हर दिन भारी मात्रा में फाउंडेशन का इस्तेमाल करने से चेहरे की चमक धीरे-धीरे कम होने लगती है। खासतौर पर अगर आप नियमित रूप से चेहरे पर किसी सस्ते से फाउंडेशन का इस्तेमाल करते हैं, तो इसकी वजह से आपका चेहरा डल होने लगता है।

कम उम्र में एजिंग की शुरुआत

फाउंडेशन को सही से न हटाने की वजह से भी आपको एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल, अगर फाउंडेशन को सही से साफ नहीं किया गया, तो यह स्किन को सांस लेने से रोकता है, जिससे समय से पहले झुर्रियां आ सकती हैं।

बरसात में गलती से भी इन 7 पेड़ों को न लगाएं, सांपों का बन जाता है अड्डा

प्राकृतिक हरियाली हमारी जिंदगी में सुकून लाती है, लेकिन अगर सावधानी न बरती जाए तो यह जानलेवा भी साबित हो सकती है। इस मानसून में अपने घर और आसपास के गार्डन या खेत में इन पौधों को पहचानें और उनसे उचित दूरी बनाए रखें।

बरसात का मौसम हरियाली और ताजगी लेकर आता है, लेकिन इसी के साथ बढ़ता है सांपों का खतरा। बारिश में जमीन गीली हो जाती है, बिलों में पानी भर जाता है और सांप निकलकर सूखे और गर्म स्थानों की तलाश में घरों की ओर रुख करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ खास पेड़ और पौधे ऐसे हैं जो सांपों को विशेष रूप से आकर्षित करते हैं? बारिश के मौसम में सांप अक्सर इन पेड़ों की जड़ों, झाड़ियों और छालों में छिप जाते हैं या लिपटकर आराम करते हैं।

अगर आप अपने घर, खेत, बगीचे या ऑफिस के आसपास इन पौधों को लगाते हैं तो आपको सावधान होने की जरूरत है। प्राकृतिक हरियाली हमारी जिंदगी में सुकून लाती है, लेकिन अगर सावधानी न बरती जाए तो यह जानलेवा भी साबित हो सकती है। इस मानसून में अपने घर और आसपास के गार्डन या खेत में इन पौधों को पहचानें और उनसे उचित दूरी बनाए रखें।

केले का पेड़

केले का पौधा सांपों का सबसे पसंदीदा ठिकाना होता है। केले का पेड़ गीला, छायादार और मुलायम होता है, जो सांपों को बेहद पसंद आता है। बारिश के दिनों में इसकी जड़ें और तनों के बीच की जगह सांपों के छिपने के लिए आदर्श बन जाती है। ऐसे में केले के पौधे को घर के बहुत पास न लगाएं। बड़े पौधों में ये आसानी से छिप जाते हैं।

पीपल और बरगद

पीपल और बरगद का पेड़ गर्मी में छांव देने के साथ ही खतरे का घर भी होते हैं। ये दोनों पेड़ अपने मोटे तनों और हवाई जड़ों के कारण सांपों को छिपने और ऊपर चढ़ने के लिए सबसे उपयुक्त लगते हैं। बारिश में इनकी नमी और अंधेरा सांपों को बहुत भाता है। बरसात के मौसम में इन पेड़ों के पास जाने से बचें और सावधानी रखें।

बांस का झाड़

बांस के पेड़ घने होते हैं और इनके नीचे की ज़मीन अक्सर नम रहती है। यह माहौल सांपों को बिल बनाने या आराम करने के लिए उपयुक्त लगता है। कई बार सांप बांस के खोखले हिस्से में भी छिप जाते हैं। ये सांप के लिए बिल या सुरंग जैसा होता है। इसलिए बांस को गार्डन में न लगाएं। बारिश में बांस के पेड़ों में सांप छिपे हो सकते हैं।

तुलसी के पास झाड़ियां

तुलसी का पौधा आस्था से जुड़ा है और पवित्र माना जाता है, लेकिन इसके आस-पास झाड़ियां या घास उग जाएं तो वो सांपों के छिपने की जगह बन जाती हैं। खासकर जब आप तुलसी के पास गमलों या बेकार चीज़ों को जमा करते हैं। ऐसे में बारिश के मौसम में विशेष तौर पर तुलसी के आसपास साफ-सफाई बनाए रखें।

नीम का पेड़

नीम एंटीबैक्टीरियल होने के बावजूद सांपों को गर्म और सुरक्षित माहौल देता है, खासकर जब इसके नीचे सूखी पत्तियाँ जमा हो जाती हैं। नीम के पेड़ पर सांप डेरा जमा सकते हैं। इसलिए अगर घर के आसपास या गार्डन में नीम लगी हो तो नियमित साफ-सफाई जरूर रखें।

सफेदा और अर्जुन

ये ऊंचे और घने पेड़ बारिश में सांपों के लिए सुरक्षित स्थान बन जाते हैं। इन पेड़ों पर चढ़ने या झाड़ियों में छिपने के लिए मानसून का मौसम उपयुक्त समय होता है। इसलिए इन पेड़ों को मुख्यद्वार या खिड़की के पास न लगाएं।

कनेर और दूध वाले पौधे

कनेर जैसे फूलदार पौधे और जिन पौधों से दूध निकलता है, वे भी सांपों को आकर्षित करते हैं। इनमें घनी पत्तियां और छिपने की पर्याप्त जगह होती है। घर पर इन पेड़ों को लगाने से बचें। साथ ही घर के आसपास ऐसे पौधे लगे हैं तो बच्चों को दूर रखें।

बच्चों का बढ़ता वजन दे रहा गंभीर बीमारियों को न्योता, जानिए मोटापे की वजह और बचाव के आसान तरीके

बचपन में मोटापा बढ़ने के लिए कई कारण जिम्मेदार हो सकते हैं। बच्चों में शारीरिक गतिविधि की कमी जैसे बाहर कम खेलना, दौड़–भाग में कमी, आउटडोर गेम्स में न हिस्सा लेना इसका प्रमुख कारण है।

मोटापा वैश्विक स्तर पर बढ़ती एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या है, सभी उम्र के लोगों में इसका खतरा देखा जा रहा है। मोटापा के कारण टाइप-2 डायबिटीज से लेकर हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल से लेकर कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा हो सकता है। यही कारण है कि स्वास्थ्य विशेषज्ञ सभी लोगों को अपने वजन को कंट्रोल में रखने के लिए निरंतर प्रयास करते रहने की सलाह देते हैं।

बच्चों में बढ़ते मोटापा की समस्या को सेहत के नजरिए से काफी गंभीर माना जाता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ सभी माता-पिता को सलाह देते हैं कि वह सुनिश्चित करें कि बच्चे का वजन बढ़ने न पाए। कम उम्र में मोटापा सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक और सामाजिक समस्याएं भी पैदा कर सकता है।

अगर इसे समय रहते रोक लिया जाए तो भविष्य की कई बीमारियों से बचा जा सकता है। इसके लिए जरूरी है जागरूकता, सही लाइफस्टाइल और दिनचर्या में छोटे-छोटे बदलाव। आइए इस बारे में आगे विस्तार से समझते हैं।

कम उम्र में वजन बढ़ने का कारण

बचपन में मोटापा बढ़ने के लिए कई कारण जिम्मेदार हो सकते हैं। बच्चों में शारीरिक गतिविधि की कमी जैसे बाहर कम खेलना, दौड़-भाग में कमी इसका प्रमुख कारण है। ज्यादा बैठे रहने की आदत जैसे ऑनलाइन क्लास, फास्ट फूड और प्रोसेस्ड चीजों के अधिक सेवन की आदत को स्वास्थ्य विशेषज्ञ मोटापे का प्रमुख कारण मानते हैं।

मानसिक रोगों का भी बढ़ जाता है खतरा?

कम उम्र में वजन बढ़ने की स्थिति भविष्य में अवसाद, चिंता और तनाव जैसी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को भी बढ़ाने वाली हो सकती है। बच्चों के समग्र स्वास्थ्य को ठीक रखने और इस प्रकार की जटिलताओं के जोखिम को कम करने के लिए शारीरिक की वजन कंट्रोल में रखने के लिए प्रयास बहुत आवश्यक हैं। कम उम्र से ही कुछ उपाय करके बच्चे के वजन को कंट्रोल रखा जा सकता है।

वजन बढ़ने से कैसे रोका जाए?

कुछ बातों का ध्यान रखकर न सिर्फ वजन को कंट्रोल रखा जा सकता है साथ ही उन्हें भविष्य में गंभीर बीमारियों से बचाए रखने में भी मदद मिल सकती है।

स्वस्थ भोजन और नियमित शारीरिक गतिविधि सबसे आवश्यक है। सुबह का नाश्ता दैनिक आहार का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें मौसमी फल-जूस, दूध और डेयरी उत्पादों को शामिल करें। सुनिश्चित करें कि आप पर्याप्त नींद ले रहे हैं। जिन लोगों की नींद पूरी नहीं होती है उनमें मोटापे का जोखिम अधिक होता है। इसके साथ अपना स्क्रीन टाइम भी कम कर लें।

इन बातों पर भी दें ध्यान

वजन को कंट्रोल रखने के लिए कम उम्र से ही कुछ आदतों को दिनचर्या में जरूर शामिल करें। हर दिन कम से कम 45 मिनट तेज चलना, दौड़ना, योग या डांस जैसी गतिविधि जरूर करें।

घर का बना, कम तेल वाला और संतुलित भोजन करें। फलों, सब्जियों, दालों की मात्रा बढ़ाएं।

कोल्ड ड्रिंक, केक, बिस्किट और पैकेज्ड स्नैक्स का सेवन कम से कम करें।

मोबाइल या लैपटॉप पर समय सीमित करें। 7–8 घंटे की नींद शरीर को रिलैक्स करती है और वजन कंट्रोल रखने में भी सहायक है।

–30–

ब्रिटेन के पब में बिकेगी फेणी और ताड़ी, सालाना इतने बिलियन डॉलर का होगा एक्सपोर्ट

नई दिल्ली, एजेंसी। भारत के पारंपरिक शिल्प पेय जैसे गोवा का फेणी, नासिक की हस्तशिल्प वाइन और केरल का ताड़ी अब यूके में भी मान्यता पाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक गुरुवार को भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (एफटीए) पर हस्ताक्षर होने के बाद यह संभव हो पाया है।

इस समझौते के बाद भारतीय पारंपरिक पेय न सिर्फ भौगोलिक संकेत (जीआई) संरक्षण पाएंगे, बल्कि यूके जैसे विकसित बाजारों में भी पहुंच बना सकेंगे, जहां प्राकृतिक और ऑर्गेनिक उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ रही है। इन पेयों को शामिल करने से ब्रिटेन में रहने वाले लोगों को अलग स्वाद और खास फ्लेवर मिलेगा।

GI टैग के साथ होगी बिक्री

एफटीए से न सिर्फ पारंपरिक भारतीय शिल्प पेय यूके के स्टोर में स्कॉच व्हिस्की और अन्य ब्रांड्स के साथ शेल्फ पर दिखेंगे, बल्कि यह होटल-रेस्टोरेंट जैसे विशेष बाजारों तक भी पहुंचने में मदद करेगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के एक अधिकारी यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया, गोवा का फेणी, नासिक की वाइन और केरल की ताड़ी जैसे भारतीय शिल्प पेय अब भौगोलिक संकेत (जीआई) संरक्षण के साथ यूके के हाई-एंड रिटेल और हॉस्पिटैलिटी चैन में जगह पाएंगे।

2030 तक इतने बिलियन का होगा एक्सपोर्ट

सरकार के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि वह भारतीय अल्कोहलिक ड्रिंक्स के निर्यात को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। हालांकि यह क्षेत्र नया है, लेकिन सरकार को उम्मीद है कि 2030 तक भारत का अल्कोहलिक ड्रिंक्स का निर्यात 1 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा, जो फिलहाल 370.15 मिलियन डॉलर है। इस साल अप्रैल में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) ने कहा था कि भारतीय अल्कोहलिक ड्रिंक्स के पास वैश्विक बाजार में बड़ी संभावनाएं हैं और देश में जिन, बीयर, वाइन और रम जैसे कई क्वालिटी प्रोडक्ट्स उपलब्ध हैं जो विदेशों में बेचे जा सकते हैं। अभी भारत दुनिया में अल्कोहलिक ड्रिंक्स के निर्यात में 40वें नंबर पर है और आने वाले वर्षों में टॉप 10 निर्यातकों में शामिल होने का लक्ष्य है। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का अल्कोहलिक ड्रिंक्स का निर्यात 2,200 करोड़ रुपये से ज्यादा रहा। यूएई, सिंगापुर, नीदरलैंड, तंजानिया, अंगोला, केन्या और रवांडा इसके प्रमुख बाजार रहे।

आयकर रिटर्न भरने से पहले इन 5 टैक्सेबल इनकम सोर्सेज की कर लें जानकारी, वरना हो सकता है नुकसान

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आटीआर भरने से पहले टैक्सपेयर्स को इन 5 टैक्सेबल इनकम सोर्सेज को समझना जरूरी है। क्योंकि इससे उन्हें सही ITR फॉर्म चुनने में आसानी होगी और किसी भी तरीके का नुकसान नहीं होगा।

अगर आप करदाता हैं और वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अपना इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की योजना बना रहे हैं, तो आपको अपनी आय के पांच प्रमुख स्रोतों को समझना जरूरी है। ये सोर्स वेतन, संपत्ति से किराये की आय, संपत्ति जैसे सोना, शेयर या रियल एस्टेट बेचने से होने वाला लाभ, व्यवसाय से मुनाफा, और अन्य स्रोतों जैसे सावधि जमा (एफडी) पर ब्याज है। हर करदाता की आय इनमें से एक या अधिक स्रोतों से हो सकती है, उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति वेतन और किराये की आय के साथ-साथ छोटा व्यवसाय चला सकता है या कोई व्यवसायी अपनी कंपनी से वेतन ले सकता है। आईटीआर भरने से पहले अपनी टैक्सेबल इनकम के बारे में सही जानकारी होना जरूरी है। इससे सही आईटीआर फॉर्म चुनने में सहायता मिलेगी।

मिंट की रिपोर्ट में दिल्ली की चार्टर्ड अकाउंटेंट और पीडी गुप्ता एंड कंपनी की पार्टनर सीए प्रतिभा गोयल कहती हैं कि हालांकि यह आम नहीं है, लेकिन कुछ मामलों में करदाता की आय इन सभी पांच स्रोतों से हो सकती है। ऐसे में, मामले की बारीकियों के आधार पर आईटीआर-3 या आईटीआर-4 का उपयोग करना होगा।

आय के पांच प्रमुख स्रेत

वेतन- इसमें मूल वेतन, भत्ते, बोनस और अन्य सुविधाएं शामिल हैं। अगर आपकी आय केवल वेतन से है, तो आप आईटीआर-1 के जरिए रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।

संपत्ति से आय- इसमें आपकी स्वामित्व वाली संपत्ति से किराये की आय शामिल है। अगर आपके पास ऐसी आय है, तो आप आईटीआर-1 का उपयोग कर सकते हैं।

कैपिटल गेन- यह शेयर, म्यूचुअल फंड या रियल एस्टेट बेचने से होने वाला लाभ है, जो अल्पकालिक या दीर्घकालिक हो सकता है। अगर पूंजीगत लाभ 1.25 लाख रुपये से कम है, तो आईटीआर-1, और अगर इससे अधिक है, तो आईटीआर-2 का उपयोग करें।

व्यवसाय या पेशा- इसमें स्वरोजगार, फ्रीलांसिंग या व्यवसाय से होने वाला मुनाफा शामिल है। खुद का उद्यम, फ्रीलांसर या छोटे व्यवसायी इस श्रेणी में आते हैं। इस तरह की आय के लिए आईटीआर-4, आईटीआर-5 या आईटीआर-6 का उपयोग करना होगा, जो व्यवसाय के प्रकार पर निर्भर करता है।

अन्य स्रोत- इस श्रेणी में ब्याज आय, शेयरों से लाभांश, लॉटरी जीत और उपहार शामिल हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप CoinDCX या बिग बॉस जैसे किसी टीवी शो से इनाम जीतते हैं, तो आपकी कमाई अन्य स्रोतों में आएगी।

नुकसान 'जीरो' और फायदा 'फुल'! पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में मिलेंगे 9250 रुपए हर महीने

अगर आप शेयर बाजार की अनिश्चितता से परेशान हैं और बिना किसी जोखिम के पक्का रिटर्न चाहते हैं, तो पोस्ट ऑफिस की कुछ स्कीमें आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकती हैं। देशभर में पोस्ट ऑफिस की कई गारंटीड रिटर्न वाली योजनाएं लोगों के बीच काफी पॉपुलर हैं। ऐसी ही एक स्कीम है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम (POMIS), जिसका फायदा शादी के बाद आप अपनी फैमिली के साथ उठा सकते हैं। इस स्कीम में एक बार पैसा लगाकर आप लंबे समय तक हर महीने अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं।

बच्चों के नाम पर भी खुलवा सकते हैं अकाउंट

आप इस योजना को अपने 10 साल से बड़े बच्चे के नाम पर भी खुलवा सकते हैं। इससे हर महीने मिलने वाला ब्याज बच्चे की स्कूल फीस या अन्य खर्चों में काम आ सकता है। यह स्कीम उन कपल्स के लिए भी बेहतर है जो शादी के बाद एक मजबूत फाइनेंशियल प्लान बनाना चाहते हैं।

क्या है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम?

इंडिया पोस्ट की वेबसाइट के मुताबिक, POMIS में आप सिर्फ 1,000 रुपये से अकाउंट खोल सकते हैं। इसमें सिंगल या ज्वाइंट दोनों तरह के अकाउंट की सुविधा है। सिंगल अकाउंट में आप ज्यादा से ज्यादा 9 लाख रुपये जमा कर सकते हैं, जबकि ज्वाइंट अकाउंट में यह सीमा 15 लाख रुपये तक है। इसमें हर महीने ब्याज का भुगतान होता है। फिलहाल इस स्कीम पर 7.4% सालाना ब्याज मिल रहा है। इस स्कीम की मैच्योरिटी 5 साल की होती है, जिसे आप चाहें तो 5 साल और बढ़ा सकते हैं।

कैसे काम करती है POMIS स्कीम?

इस योजना में सालाना मिलने वाला ब्याज 12 हिस्सों में बांट दिया जाता है और हर महीने आपके अकाउंट में ट्रांसफर होता रहता है। अगर आप महीने का ब्याज नहीं निकालते तो यह आपके पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में जमा होता रहेगा। मैच्योरिटी पर आपका पूरा मूलधन भी आपको वापस मिल जाता है।

कितनी मिलेगी महीने की कमाई?

अगर आप अपने जीवनसाथी के साथ ज्वाइंट अकाउंट खोलकर 15 लाख रुपये निवेश करते हैं, तो आपको सालाना करीब 1 लाख 11 हजार रुपये ब्याज मिलेगा। यानी हर महीने लगभग 9,250 रुपये की तय इनकम होगी। अगर आप सिंगल अकाउंट में 9 लाख रुपये लगाते हैं तो आपको सालाना करीब 66,600 रुपये ब्याज मिलेगा और हर महीने करीब 5,550 रुपये की आमदनी होगी। खास बात यह है कि इसमें कोई जोखिम नहीं है और आपका पैसा पूरी तरह सुरक्षित रहता है।

फिलिस्तीन को कौन-कौन से मुल्क मानते हैं एक आजाद देश?

मॉस्को, एजेंसी। मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष के बीच फ्रांस ने फिलिस्तीन को लेकर बड़ा एलान किया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने ऐलान किया है कि उनका देश जल्द ही फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर मान्यता देगा। ये ऐलान उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर किया और कहा कि सितंबर में होने वाली संयुक्त राष्ट्र के दौरान इसे औपचारिक रूप से घोषित किया जाएगा।

फ्रांस ऐसा करने वाला G7 ग्रुप का पहला बड़ा पश्चिमी देश बन जाएगा। फ्रांस के इस फैसले को लेकर दुनियाभर में हलचल मच गई है। फिलिस्तीनी अथॉरिटी ने इस पर खुशी जताई है जबकि इजराइल ने तीखी आपत्ति दर्ज कराई है।

इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस फैसले की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि फ्रांस का ये कदम आतंकवाद को इनाम देने जैसा है और गाजा की तरह एक और ईरानी मोहरे को जन्म देने का खतरा बढ़ाता

है।

नेतन्याहू ने कहा कि अगर फिलिस्तीनी राज्य बनता है, तो वो इजराइल के साथ शांति से जीने का माध्यम नहीं, बल्कि उसे मिटा देने का लॉन्चपैड साबित होगा। साफ कहें तो फिलिस्तीन को इजराइल के साथ नहीं, बल्कि इजराइल की जगह चाहिए!

अब तक कौन-कौन देश मानते हैं फिलिस्तीन को?

फ्रांस से पहले 147 देशों ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर मान्यता दी है। यानी संयुक्त राष्ट्र के कुल 193 सदस्य देशों में से लगभग 75% देश फिलिस्तीन को एक देश मानते हैं। ये देश मुख्य रूप से एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और अरब दुनिया से हैं। इनमें से कुछ प्रमुख देश हैं भारत, चीन, ब्राजील, रूस, साउथ अफ्रीका।

अरब देशों में सऊदी अरब, मिस्र, यूएई, कतर। एशियाई देशों में इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। वहीं अफ्रीकी देशों की बात करें तो नाइजीरिया, केन्या, अल्जीरिया फिलिस्तीन को मान्यता दे चुके हैं। लैटिन अमेरिकी देशों में वेनेजुएला, क्यूबा, अर्जेंटीना शामिल हैं।

यूरोप के क्या हाल हैं?

यूरोप के कई देश धीरे-धीरे फिलिस्तीन को मान्यता दे रहे हैं। स्वीडन 2014 में ऐसा करने वाला पहला पश्चिमी यूरोपीय देश था। 2024 में हालात और बदले। 22 मई 2024 को नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन ने साथ में फिलिस्तीन को मान्यता दी। 4 जून 2024 को स्लोवेनिया ने भी फिलिस्तीन को एक देश माना। माल्टा और बेल्जियम जैसे देश भी इस पर चर्चा कर रहे हैं। इन देशों ने कहा कि वो 1967 की सीमा के अनुसार फिलिस्तीन को मान्यता देंगे, यानी वेस्ट बैंक, पूर्वी यरुशलम और गाज़ा पट्टी को फिलिस्तीन का हिस्सा मानते हैं।

G7 देश और अमेरिका की स्थिति

आज की तारीख में G7 के कोई भी देश, यानी अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, जापान, कनाडा और खुद फ्रांस फिलिस्तीन को औपचारिक मान्यता नहीं देते थे। अब फ्रांस इस ग्रुप का पहला देश बन गया है जो यह कदम उठा रहा है। अमेरिका और ब्रिटेन फिलहाल दो-राष्ट्र समाधान की बात तो करते हैं, लेकिन फिलिस्तीन को अलग राष्ट्र के तौर पर मान्यता देने से बचते रहे हैं।

इतिहास: कब-कब मिली मान्यता?

1988: यासिर अराफात ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया। इसके तुरंत बाद 80 से ज्यादा देशों ने मान्यता दी।

1993: ऑस्लो समझौते में इजराइल और फिलिस्तीन ने सीधी बातचीत की, लेकिन अलग राज्य बनने की उम्मीद अधूरी रह गई।

2012: UN महासभा ने फिलिस्तीन को नॉन-मेंबर ऑब्जर्वर स्टेट का दर्जा दिया।

2014: स्वीडन ने पश्चिमी यूरोप से पहली बार मान्यता दी।

फिलिस्तीन को मान्यता क्यों मायने रखती है?

इससे फिलिस्तीन की वैश्विक स्थिति मजबूत होती है। दूसरा कि इजराइल पर दबाव बढ़ता है कि वो अंतरराष्ट्रीय नियमों का पालन करे। दो-राष्ट्र समाधान (इज़राइल और फिलिस्तीन का अलग-अलग वजूद) को बल मिलता है। गाज़ा में युद्ध और नागरिकों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ वैश्विक एकता का संकेत मिलता है।

फ्रांस की स्थिति क्यों खास है?

फ्रांस में पश्चिमी यूरोप की सबसे बड़ी मुस्लिम और सबसे बड़ी यहूदी आबादी है। इसलिए वहां मिडिल ईस्ट का कोई भी विवाद घरेलू तनाव में बदल सकता है। यही वजह है कि फ्रांस का यह कदम कूटनीतिक रूप से बहुत अहम माना जा रहा है। फ्रांस के इस ऐलान के बाद यह देखना दिलचस्प होगा कि अब जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका जैसे बड़े पश्चिमी देश क्या रुख अपनाते हैं।

फिलीपींस में तूफान 'को-मे' का कोहराम, 25 की मौत; 2.78 लाख लोगों को सुरक्षित निकाला गया

मनीला। फिलीपींस में पिछले एक हफ्ते से जारी मूसलधार बारिश और भूस्खलन के बीच अब ट्रॉपिकल तूफान 'को-मे' ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहे फिलीपींस के लिए यह तूफान एक और बड़ा झटका साबित हुआ है। ऐसे में सरकार और अंतरराष्ट्रीय सहयोग की भूमिका अहम बन जाती है ताकि लाखों लोगों को सुरक्षित और आवश्यक मदद मिल सके।

इस खतरनाक तूफान के कारण अब तक कम से कम 25 लोगों की जान जा चुकी है और लगभग 2.78 लाख लोगों को अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर जाना पड़ा है। तूफान शुक्रवार को देश के उत्तरी पहाड़ी इलाकों से गुजरा। 'को-मे' नाम का यह तूफान गुरुवार की रात पांगासिनान प्रांत के अग्नो कस्बे में 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकराया। इसके झोंकों की गति 165 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई थी। शुक्रवार सुबह तक इसकी ताकत थोड़ी कम हुई और यह 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूर्वोत्तर दिशा की ओर बढ़ता दिखा।

तूफान ने देश में पहले से ही चल रही मौसमी बारिश को और ज्यादा तीव्र बना दिया। पिछले एक हफ्ते से लगातार हो रही बारिश से कई इलाकों में बाढ़, पेड़ों के गिरने, भूस्खलन और बिजली के झटकों से लोगों की जान गई है। फिलहाल आठ लोग लापता हैं। हालांकि, तूफान 'को-मे' से सीधे मौत की कोई पुष्टि अब तक नहीं हुई है। सरकार ने राजधानी मनीला में शुक्रवार को लगातार तीसरे दिन स्कूल बंद रखने का आदेश दिया है। लुजोन के मुख्य उत्तरी इलाके के 35 प्रांतों में कक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं।

चीन है थाईलैंड-कंबोडिया जंग का स्पॉन्सर?

थाईलैंड। धरती पर जंग का एक और नया फ्रंट खुल चुका है। दक्षिण पूर्वी एशिया के दो देशों की जंग शुरू हो चुकी है। ये दो देश हैं थाईलैंड और कंबोडिया। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच पुराना सीमा विवाद है, लेकिन इस विवाद के जंग में बदलने का समय बहुत महत्वपूर्ण है। इस जंग का प्रायोजक है चीन। चीन को एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाना है और इसके लिए वो थाईलैंड का इस्तेमाल कर रहा है। 24 जुलाई की सुबह शुरू हुई जंग में अबतक 14 लोग मारे जा चुके हैं। दोनों देश एक दूसरे पर MLRS हमले कर रहे हैं। थाईलैंड लड़ाकू विमानों से भी हमले कर रहा है। इस जंग के शुरू होने के पीछे क्या कारण है और चीन इससे क्या हासिल करना चाहता है?

24 जुलाई की सुबह एशिया में नई जंग शुरू हो गई। ये जंग है थाईलैंड वर्सेज कंबोडिया। दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आ गईं। सीमा पर दोनों देशों के सैनिकों ने गोलीबारी शुरू कर दी। कंबोडिया के सैनिक बड़ी तादाद में सीमा पर जमा हुए और हमले शुरू कर दिए। कंबोडियाई सेना ने थाईलैंड पर MLRS यानी मल्टीपल लॉन्च्ड रॉकेट सिस्टम से हमले शुरू कर दिए। थाईलैंड के कई शहरों में तबाही का दौर शुरू हो गया।

थाईलैंड के तीन प्रांतों पर कंबोडिया का बारूद बरसने लगा। सीमा के करीब स्कूलों में बच्चों को बंकरों में भेजा जाने लगा। थाईलैंड कंबोडिया की सीमा पर बसे गांवों में अफरा-तफरी और भगदड़ मच गई। थाईलैंड की वायुसेना ने कंबोडिया पर हमले शुरू कर दिए। F-16 से फायर किया गया एक बम कंबोडिया के गैस स्टेशन पर गिरा। दोनों देशों के बीच सीमा विवाद पुराना है, इससे पहले मई के महीने में भी दोनों देशों की सेनाओं की झड़प हुई थी, लेकिन तब मामला इतना ज्यादा विध्वंसक नहीं हुआ था।

24 जुलाई की सुबह दोनों देशों की सेनाओं के बीच इन्फैंट्री और आर्टिलरी की जंग शुरू हुई और थाईलैंड की वायु सेना के हमले भी शुरू हो गए। थाईलैंड के सुरिन प्रांत और कंबोडिया के ओडर मेंची प्रांत की सीमा पर विवाद शुरू हुआ। सुबह करीब 7:30 बजे, थाईलैंड की टुकड़ी ने ता मुएन थोम मंदिर के आसपास कंबोडिया का एक ड्रोन देखा। इसी दौरान सीमा 6 कंबोडियाई सैनिक थाईलैंड की सीमा में घुसने की कोशिश करते देखे गए।

सुबह करीब 8:20 बजे, कंबोडियाई सेना की ओर से थाईलैंड के एक मिलिट्री पोस्ट पर अचानक गोलीबारी शुरू कर दी गई। यह पोस्ट ता मुएन थोम मंदिर से कुछ ही दूरी पर है।

हथकड़ी-हेलमेट और बुलेटप्रूफ जैकेट पहना कोर्ट में किया पेश... बांग्लादेश में पूर्व चीफ जस्टिस को भी भेजा गया जेल

ढाका, एजेंसी। ढाका की एक अदालत ने बांग्लादेश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एबीएम खैरुल हक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। खैरुल हक को जत्राबाड़ी पुलिस स्टेशन के पास हुए विद्रोह के दौरान हुई हत्या के एक मामले में गिरफ्तार किया गया है। यह फैसला हक को उनके आवास में डिटेन करने के कुछ घंटों बाद आया। बांग्लादेश के इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब किसी न्यायाधीश को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया हो।

टीवी फुटेज में दिखाया गया कि पुलिस हक के हाथों में हथकड़ी लगाकर, हेलमेट और बुलेटप्रूफ जैकेट पहनाकर अदालत ले गई। बताया जा रहा है कि पुलिस रात के करीब 8 बजे हक को जेल वैन से ढाका के पुराने इलाके में स्थिति अदालत में ले गई। जहां उन्हें

सीढ़ियों के रास्ते मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ले जाया गया

किस मामले में किया गया गिरफ्तार

दरअसल, पिछले साल जत्राबाड़ी में एक पुलिस चौकी के पास हिंसक आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन के दौरान एक छात्र कार्यकर्ता अब्दूल कैयूम अहद पर धारदार हथियारों से हमला हुआ था और उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसी मामले में पूर्व मुख्य न्यायाधीश एबीएम खैरुल हक को आरोपी ठहराकर जेल भेज दिया गया था। इस आंदोलन को तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग सरकार को उखाड़ फेंकने वाला विद्रोह कहा जाता है।

हत्या में 1,000 से 2,000 लोग शामिल

एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट एम सनाउल्लाह ने किशोर अब्दुल कैयूम अहद की हत्या के मामले सुनवाई करते हुए हक को जेल भेजने का आदेश दिया। इस मामले में हक को एक आरोपी के रूप में नामित किया गया था, जबकि पुलिस ने कहा कि जत्राबाड़ी इलाके में हुई इस हत्या में 1,000 से 2,000 लोग शामिल थे। अदालत में भीड़ नारे लगा कर पूर्व मुख्य न्यायाधीश खैरुल हक को फासीवादी शासन का सहयोगी बता रही थी।

हक के बचाव के लिए नहीं था कोई वकील

बांग्लादेश के एक समाचार पत्र में बताया कि अदालती कार्यवाही के दौरान हक 40 मिनट तक कटघरे में खड़े रहे, लेकिन अदालत में कोई भी वकील उनके बचाव पक्ष के लिए खड़ा नहीं हुआ। अभियोजन पक्ष मांग कर रहा था कि उन्हें जेल में डाल दिया जाए। अभियोजन पक्ष के एक वकील ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश को गिरफ्तार करने के लिए मुहम्मद यूनुस की सरकार को धन्यवाद भी दिया। अदालत में मौजूद अधिकारियों ने कहा कि वह बांग्लादेश के इतिहास में पहले मुख्य न्यायाधीश थे जिन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। बता दें कि हक ने 2010 से 2011 तक देश के 19वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभाला था। वह अपने कार्यकाल के दौरान लिए गए कई ऐतिहासिक फैसलों के लिए जाने जाते थे। उन्होंने 2011 में एक फैसला लिया था, जिसमें उन्होंने बांग्लादेश की गैर-पक्षपाती कार्यवाहक सरकार प्रणाली को असंवैधानिक घोषित कर दिया था।

बिहार सरकार ने कहां डाले 71 हजार करोड़? डिफॉल्टर लिस्ट के टॉप 5 मंत्रालय किसके पास

तेजस्वी के कार्यकाल से भी जुड़े तार

पटना। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी तापमान चढ़ा हुआ है। वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया चल रही है, जिस पर सियासी घमासान हो रहा है। इस बीच नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की वित्त पर साल 2023-24 की रिपोर्ट विधानसभा के मॉनसून सत्र में पेश हो गई, जिसमें बड़े सवाल खड़े किए हैं। कैग रिपोर्ट मे बताया गया है कि बिहार सरकार 70,877 करोड़ रुपए के कामों के उपयोगिता प्रमाणपत्र जमा नहीं कर पाई है। उसने इसको लेकर नीतीश कुमार सरकार की खिंचाई की।

अगर सरकार उपयोगिता प्रमाणपत्रों को जमा नहीं करती या फिर उन्हें लंबित रखती है तो गबन और धन के दुरुपयोग का खतरा बढ़ जाता है। जिन 70,877 करोड़ रुपए का जिक्र कैग की रिपोर्ट में किया गया है उनमें से 14,452। 38 करोड़ रुपए वित्त वर्ष 2016-17 तक की अवधि के हैं। इसकी वजह से आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के कार्यकाल से भी तार जुड़ रहे हैं। उस समय तेजस्वी यादव उपमुख्यमंत्री थे।

रिपोर्ट में बताया गया है कि डिफॉल्टर विभागों में पंचायती राज सबसे ऊपर है, जिसने 28,154। 10 करोड़ रुपए के प्रमाणपत्र जमा नहीं किए हैं। इसके बाद शिक्षा (12,623। 67 करोड़ रुपए), शहरी विकास (11,065। 50 करोड़ रुपए), ग्रामीण विकास (7,800। 48 करोड़ रुपए) और कृषि (2,107। 63 करोड़ रुपए) शामिल हैं। जिस समय 2015 में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने मिलकर महागठबंधन की सरकार बनाई थी उस समय पंचायती राज जेडीयू के कपिल देव कामत, शिक्षा मंत्रालय जेडीयू के अशोक चौधरी, शहरी विकास मंत्रालय जेडीयू के महेश्वर हजारी, ग्रामीण विकास मंत्रालय जेडीयू के श्रवण कुमार और कृषि मंत्रालय आरजेडी के राम विचार राय को दिया गया था। वहीं, तेजस्वी यादव तीन मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली थी। उन्होंने अपने पास सड़क निर्माण, भवन निर्माण, पिछड़ा वर्ग विकास मंत्रालय रखा था। इसके अलावा तेज प्रताप यादव के पास भी मंत्रालय का जिम्मा था, जिसमें स्वास्थ्य मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय शामिल था।

अभी किसके पास कौन सा मंत्रालय

बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए की मौजूदा सरकार में पंचायती राज मंत्रालय बीजेपी के केदार प्रसाद गुप्ता, शिक्षा मंत्रालय जेडीयू के सुनील कुमार, शहरी विकास मंत्रालय बीजेपी के जिबेश कुमार, ग्रामीण विकास मंत्रालय जेडीयू के श्रवण कुमार और कृषि मंत्रालय बीजेपी के विजय कुमार सिन्हा के पास। इन्हीं पांच मंत्रालयों ने सबसे ज्यादा निर्धारित समय सीमा के भीतर उपयोगिता प्रमाणपत्र जमा नहीं किए हैं।

बिहार सरकार ने पिछले साल खर्च किए 2.60 लाख करोड़

कैग की रिपोर्ट में बताया गया है कि निर्धारित समय सीमा 31 मार्च, 2024 तक की थी। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि उपयोगिता प्रमाणपत्रों के अभाव में इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जो पैसा बांटा गया है वो किसी बेहतर उद्देश्य के लिए दिया गया होगा। नीतीश सरकार ने साल 2023-24 के लिए 3। 26 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा था, लेकिन वह 2। 60 लाख करोड़ रुपए खर्च कर पाई। यही नहीं, राज्य सरकार अपनी बचत 65,512। 05 करोड़ रुपए में से केवल 23,875। 55 करोड़ रुपए ही लौटा पाई है।

तेजस्वी को 4 बार मारने की कोशिश हुई, हम जानते हैं कौन कर रहा है..राबड़ी देवी का बड़ा आरोप

RJD नेता राबड़ी देवी ने बिहार में हो रहे एसआईआर का विरोध करते हुए कहा कि यह बिहार की जनता का सवाल है, उनके अधिकार का सवाल है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि उन 4 करोड़ लोगों का क्या जो राज्य से बाहर चले गए हैं? राबड़ी देवी ने कहा कि हम 5 दिनों से विधानसभा में एसआईआर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। राज्य सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। राबड़ी देवी ने कहा कि तेजस्वी यादव की जान को खतरा है। उन्हें ट्रक से मारने के 4 प्रयास किए गए। उन्होंने कहा कि हमे पता है तेजस्वी को कौन मारने की साजिश रच रहा है। राबड़ी देवी ने स्पष्ट रूप से कहा कि बीजेपी और जेडीयू से तेजस्वी को खतरा है।

"हमारे नाम का किया गलत इस्तेमाल"... वेस्टआर्कटिका ने गाजियाबाद में फर्जी दूतावास चलाने वाले हर्ष वर्धन जैन से तोड़ा नाता

नई दिल्ली, एजेंसी। गाजियाबाद के कविनगर इलाके में एक लक्जरी बंगले से फर्जी विदेशी दूतावास चलाने वाले हर्ष वर्धन जैन को यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। आरोपी खुद को वेस्टआर्कटिका जैसे काल्पनिक माइक्रोनेशन का राजदूत बताकर न केवल लोगों को गुमराह कर रहा था, बल्कि डिप्लोमैटिक नंबर प्लेट्स, फर्जी पासपोर्ट और एम्बेसी जैसी सुविधाएं इस्तेमाल कर रहा था।

अब इस मामले में खुद वेस्टआर्कटिका ने एक आधिकारिक बयान जारी कर आरोपी से पूरी तरह किनारा कर लिया है और कहा है कि हर्ष वर्धन जैन ने संगठन के नाम पर कई अनधिकृत गतिविधियां कीं, जो उनके नियमों के खिलाफ हैं। इसके साथ ही भारत की जांच एजेंसियों का पूरा सहयोग करने की भी बात कही है।

वेस्टआर्कटिका क्या है?

वेस्टआर्कटिका एक काल्पनिक माइक्रोनेशन है जिसे साल 2001 में अमेरिकी नागरिक ट्रैविस मैकहेनरी ने शुरू किया था। इसकी मुख्य गतिविधि पर्यावरणीय संरक्षण है, खासकर वेस्ट अंटार्कटिक आइस शीट को लेकर। 2014 में ये एक चैरिटेबल कॉर्पोरेशन बना और 2018 में इसे अमेरिका में टैक्स छूट मिल गई।

वेस्टआर्कटिका का बयान, वो कोई राजदूत नहीं था

वेस्टआर्कटिका ने कहा कि जैन 2016 में एक दानदाता के रूप में संगठन से जुड़ा था और उसे Honorary Consul to India की प्रतिष्ठित लेकिन सीमित भूमिका दी गई थी। उन्होंने साफ किया कि जैन को कभी भी राजनयिक शक्तियां या राजदूत का दर्जा नहीं दिया गया। उसका काम सिर्फ पर्यावरण और चैरिटी से जुड़ा था, वो भी भारत में स्वैच्छिक रूप से।

कौन-कौन सी गड़बड़ियां की?

हाल ही में उसकी गिरफ्तारी के वक्त उसके पास वेस्टआर्कटिका के नाम के फर्जी पासपोर्ट, डिप्लोमैटिक नंबर प्लेट्स और 'एम्बेसी' के तौर पर इस्तेमाल हो रहा घर पाया गया। वेस्टआर्कटिका ने अपने बयान में बताया कि संगठन के पास खुद के पासपोर्ट या डिप्लोमैटिक प्लेट्स नहीं होतीं, ऐसे में जैन का इनका निर्माण और उपयोग सीधा नियम उल्लंघन है। घर को एम्बेसी कहना और झूठे दस्तावेज़ बनाना, उनकी नीतियों के खिलाफ है।

संगठन ने उठाया सख्त कदम

वेस्टआर्कटिक ने हर्ष वर्धन जैन को अनिश्चितकाल के लिए सस्पेंड कर दिया है। संगठन ने कहा कि वह भारत की जांच एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग करेगा। साथ ही, वो अपने पूरे Honorary Consular Corps की आंतरिक ऑडिट शुरू कर चुका है, ताकि भविष्य में कोई और गलत व्यक्ति उस नाम का दुरुपयोग न कर सके। अब बारी जांच एजेंसियों की है, जो यह पता लगाएंगी कि डिप्लोमैटिक ठगी के इस खेल में और कितने चेहरे शामिल हैं।

फैंस का इंतजार खत्म, 'वॉर 2' का ट्रेलर रिलीज; ऋतिक और जूनियर एनटीआर के बीच दिखी जबरदस्त टक्कर

ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की 'वॉर 2' का ट्रेलर रिलीज हो गया है। ट्रेलर में दोनों स्टार्स के बीच जबरदस्त क्लैश देखने को मिल रहा है।

दर्शकों का इंतजार खत्म हुआ और ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की साल की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्म 'वॉर 2' का ट्रेलर आज रिलीज हो गया। ट्रेलर ऋतिक और जूनियर एनटीआर के बीच जबरदस्त क्लैश देखने को मिली, जो ये सबूत देती है कि फिल्म में दोनों के बीच हाई लेवल एक्शन देखने को मिलेगा। फिल्म का ट्रेलर रिलीज होते ही अब सोशल मीडिया पर भी छा गया है।

ऋतिक-एनटीआर ने ली शपथ

ट्रेलर की शुरुआत होती है ऋतिक रोशन के वॉइस ओवर और उनके इंटेंस लुक के साथ। चेहरे पर हल्का सा खून लगे ऋतिक एक भेड़िये के साथ नजर आते हैं। साथ में उनका वॉइस ओवर है जिसमें वो अपनी शपथ को दोहराते हैं। इसमें ऋतिक कहते हैं 'मैं शपथ लेता हूं कि मैं अपना नाम, अपनी पहचान, अपना घर-परिवार सब त्यागकर एक गुमनाम, बेनाम अनजान साया बन जाऊंगा।' इसके बाद दिखते हैं जूनियर एनटीआर और इसी तरह की एक शपथ जूनियर एनटीआर भी दोहराते हैं। वो कहते हैं, 'मैं शपथ लेता हूं, मैं वो सब करूंगा जो कोई और नहीं कर सकता। जो जंग कोई नहीं लड़ सकता, मैं लड़ूंगा।' इस दौरान ऋतिक और जूनियर एनटीआर की जिंदगी के भी अलग-अलग सीन दिखाए जाते हैं।

दिखी पूरी कास्ट की झलक

'वॉर 2' के ट्रेलर में ऋतिक और जूनियर एनटीआर समेत फिल्म की पूरी कास्ट की झलक देखने को मिली है। जिसमें फिल्म की लीड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी भी शामिल हैं। ट्रेलर के सामने आने के बाद अब फिल्म को लेकर लोगों का उत्साह और भी बढ़ गया है।

जूनियर एनटीआर का बॉलीवुड में डेब्यू

'वॉर 2' में जूनियर एनटीआर निगेटिव रोल में नजर आ रहे हैं। इस फिल्म से जूनियर एनटीआर बॉलीवुड में अपना डेब्यू कर रहे हैं। ट्रेलर में उनका अंदाज और दमदार किरदार देखकर लगता है कि जूनियर एनटीआर के लिए बॉलीवुड में शुरुआत करने के लिए 'वॉर 2' एक बेहतर विकल्प है।

14 अगस्त को रिलीज होगी फिल्म

'वॉर 2' यशराज फिल्म के स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा है। 'वॉर 2' 2019 में आई 'वॉर' का अगला पार्ट है। 'वॉर' में जहां ऋतिक रोशन के साथ टाइगर श्रॉफ प्रमुख भूमिका में नजर आए थे। वहीं इस बार 'वॉर 2' में जूनियर एनटीआर ऋतिक रोशन के साथ भिड़ंत करते नजर आएंगे। अयान मुखर्जी द्वारा निर्देशित 'वॉर 2' स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।

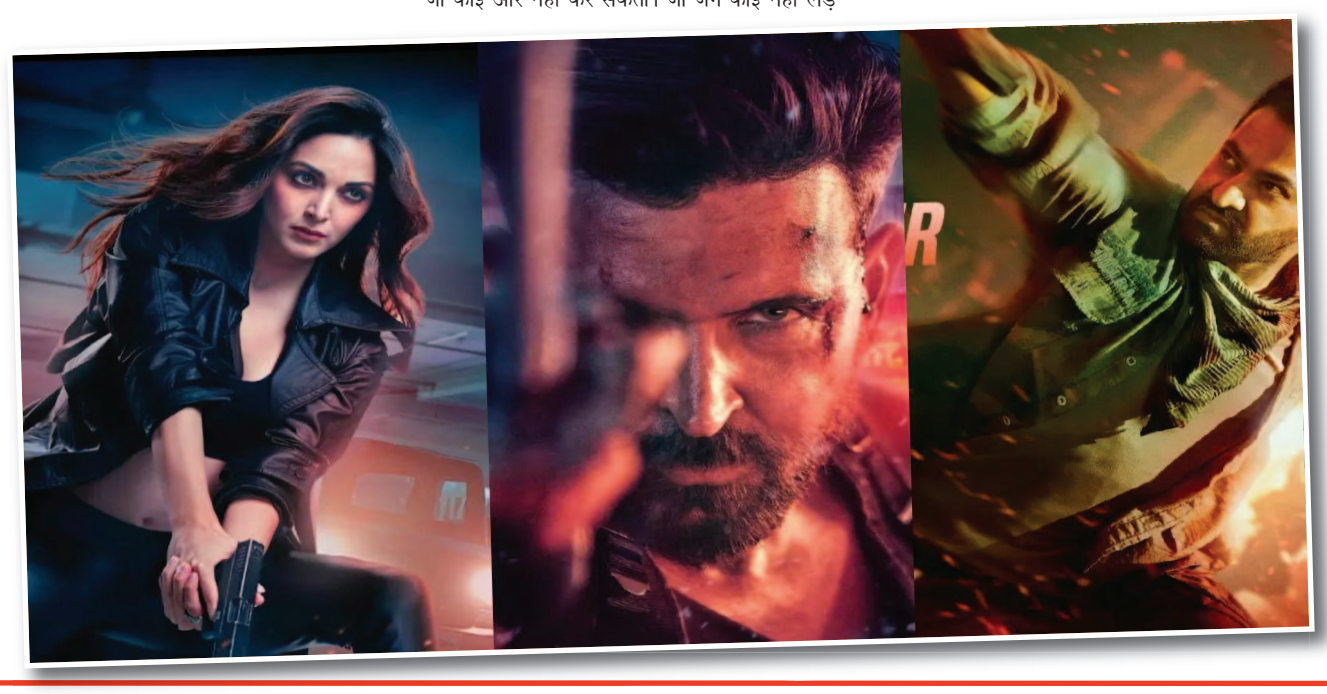

'तन्वी द ग्रेट' के फ्लॉप होने से टूट गए अनुपम, बोले- 'अब तक नहीं दे पाया कलाकारों को पैसे'

अनुपम खेर तकरीबन 23 साल बाद निर्देशक की कुर्सी पर दोबारा बैठे और 'तन्वी द ग्रेट' नाम की फिल्म लाए। फिल्म को रिलीज हुए अब एक हफ्ते का समय बीत चुका है, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई कमाल नहीं दिखा पाई। यही नहीं लगभग 50 करोड़ रुपए के बजट से बनी यह फिल्म एक हफ्ते में बॉक्स ऑफिस पर 2 करोड़ रुपए की भी कमाई नहीं कर पाई है। अनुपम खेर इस फिल्म में निर्देशक और अभिनेता होने के साथ-साथ प्रोड्यूस भी हैं। ऐसे में फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर सफल न हो पाने से अनुपम खेर निराश है। उनका कहना है कि वो अभी तक एक्टर्स की फीस भी नहीं दे पाए हैं।

रिपब्लिक से बातचीत में अनुपम खेर ने 'तन्वी द ग्रेट' के बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन न कर पाने पर निराशा जताई। निर्देशक-निर्माता ने कहा कि तन्वी ने कोई जबरदस्त कलेक्शन या कुछ भी नहीं दिया है। पिछले 10 साल से सिनेमा बिजनेस की तरह हो गया है। हमें लगता है कि अगर फिल्म की कमाई अच्छी नहीं हुई तो मतलब फिल्म अच्छी नहीं है। मैं भी इस बिजनेस वर्ल्ड का हिस्सा हूं। लेकिन जब हमने बजट बनाया वो 50 करोड़ के आस-पास हुआ। एक जेंटलमेन थे जिन्होंने कहा कि वह 50 प्रतिशत देंगे बजट का जो कि एक बड़ा अमाउंट है। सब तैयारी हो गई और फिर शूट से 1 महीने पहले मुझे बताया गया कि वह फिल्म को फाइनेंस नहीं कर पाएंगे।

अचानक फाइनेंसर के पीछे हटने से अनुपम को दूसरे स्वतंत्र फाइनेंसर पर निर्भर होना पड़ा। इसको लेकर अनुपम का कहना है कि मैंने भारत के अलावा यूएस में भी अपने कुछ दोस्तों को कॉल किया। हमारी फिल्म के 10 को-प्रोड्यूसर्स थे। यह एक तरह क्राउड फंडिंग है। मैंने उन्हें फिल्म का सिनोप्सिस भेजा और उनका फिल्म से कोई लेना-देना नहीं था। वो सभी बिजनेसमैन हैं और सिर्फ बैंक में काम करते हैं या डॉक्टर्स हैं। मैंने उन्हें कहा कि जब फिल्म रिलीज होगी तब मैं पैसे वापस कर दूंगा। लेकिन उनमें से किसी ने अभी तक मांगा नहीं।

एक्टर्स को अब तक नहीं दी फीस

यह नहीं फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर सफल न हो पाने के चलते अनुपम खेर अभी तक फिल्म की कास्ट तक को पैसे नहीं दे पाए हैं। फिल्म के एक्टर्स से अपनी दोस्ती का जिक्र करते हुए अनुपम खेर ने कहा कि सबसे मजेदार बात ये है कि मेरे सभी चार मेन एक्टर्स ने यह फैसला किया कि वो मुझसे पैसे नहीं लेंगे। अरविंद स्वामी, जैकी श्रॉफ, पल्लवी जोशी और बोमन ईरानी, मैं इन सबके पास गया और बताया कि क्या हुआ है। मैंने कहा मैं पे कर दूंगा और उन्होंने कहा कि क्या हमने मांगा?

क्रिटिक्स ने की फिल्म की तारीफ

'तन्वी द ग्रेट' की बात करें तो यह एक ऑटिस्टिक लड़की की कहानी है। रिलीज से पहले फिल्म को कान समेत अलग-अलग कई फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया, जहां फिल्म की तारीफ भी हुई। रिलीज के बाद भी क्रिटिक्स ने तो फिल्म की सराहना की, लेकिन 'तन्वी द ग्रेट' दर्शक जुटाने में सफल नहीं हो पा रही है।

वीर पहाड़िया ने भरी महफिल में तारा सुतारिया को दिया फ्लाइंग किस, यूजर्स बोले- एक्ट्रेस फिर से...

एक्टर्स तारा सुतारिया और वीर पहाड़िया का प्यार अब पूरी दुनिया के सामने आ रहा है। हालांकि, दोनों ने अभी तक अपने रिश्तों को लेकर कोई पुष्टि नहीं की है। हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में एक्ट्रेस किसी समारोह में नजर आ रही हैं, जहां उनके रूमर्ड बॉयफ्रेंड वीर पहाड़िया भी मौजूद हैं। वीडियो में दोनों एक दूसरे पर प्यार बरसाते हुए फ्लाइंग किस देते दिख रहे हैं। आइए देखें क्या है वायरल वीडियो।

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक्ट्रेस तारा सुतारिया किसी समारोह में रैंप वॉक करती नजर आ रही है। वीडियो में अभिनेत्री को क्रीम कलर का स्ट्रैपलेस गाउन और चमकदार ज्वैलरी पहने देखा जा सकता है। इसके साथ ही वह रैंप वॉक करते हुए वहां मौजूद सभी का ध्यान अपनी ओर खिंचती दिख रही हैं। रैंप के दौरान एक्ट्रेस मुस्कुरा रही हैं और इस दौरान उनके रूमर्ड बॉयफ्रेंड और अभिनेता वीर पहाड़िया भी सबसे आगे की पंक्ति में बैठकर तारा सुतारिया का हौसला अफजाई करते नजर आ रहे हैं।

एक दूसरे को फ्लाइंग किस करते नजर आए रूमर्ड कपल

वायरल वीडयो में देखा जा सकता है कि रैंप वॉक के दौरान तारा सुतारिया ने जब वीर पहाड़िया को देखा, तो उन्होंने अभिनेता को फ्लाइंग किस दिया, फिर अभिनेता ने भी एक्ट्रेस को फ्लाइंग किस दिया। भरी महफिल में दोनों अपना प्यार जताते दिखे, जिससे उनके बीच डेटिंग की अफवाहों को हवा मिल गई है। अब ये देखना है कि दोनों एक्टर्स कब अपने रिश्तों को लेकर आधिकारिक पुष्टि करते हैं।

नेटिजंस ने दी प्रतिक्रिया

वीडियो के वायरल होते ही नेटिजंस की प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं। एक यूजर ने कहा, 'आखिरकार एक्ट्रेस को वो मिल गया जिसकी वो हकदार थीं, उनके लिए बहुत खुश हूं।' दूसरे यूजर ने लिखा कि कुछ दिनों पहले वीर पहाड़िया मानुषी छिल्लर के साथ थे। इसके अलावा एक अन्य यूजर ने कहा कि फिर से एक्ट्रेस गलत लड़का चुन रही हैं।

स्वामी, प्रकाशक व मुद्रक प्रभात पांडेय द्वारा साई ऑफसेट प्रिंटर्स 40, वासुदेव भवन कैसरबाग, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 2/74, विक्रांत खंड, गोमती नगर, लखनऊ से प्रकाशित।
शाखा कार्यालय: S-15/109, सेक्टर -15, इंदिरा नगर, लखनऊ। समस्त लेख, रचनाओं एवं विज्ञापन में लेखन और विज्ञापनदाताओं के अपने विचार हैं। इसके लिए आर्यावर्त क्रांति की कोई जिम्मेदारी नहीं है। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र लखनऊ, उत्तर प्रदेश ही होगा। RNI No: UPHIN/2014/57034 Website: aryavartkranti.com
*सम्पादक: प्रभात पांडेय सम्पर्क: 9839909595, 8765295384 Email: aryavartkrantidainik@gmail.com